सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 181, नई दिल्ली, सोमवार 08 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

भगवान का इंसान के लिए संदेश : आप धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं...

03 दिल्ली पुलिस ने 400 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद किए

06 विकास की रफ्तार और घटता रोजगार

08 विधायक ने मृतक महिला प्रवीण के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

न्याय और कानून

पिंकी कुंडू महासचिव टोलवा ट्रस्ट,

न्याय और कानून किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अक्सर संविधान और अंतरराष्ट्रीय संधियों में लिखे आदर्शों से अलग दिखाई देती है। मानव के अधिकार का मूल सिद्धांत है कि हर व्यक्ति—चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से हो— उसे समान और त्वरित न्याय मिले।

भारत में संविधान समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। परंतु व्यावहारिक स्तर पर अदालतों में वर्षों की देरी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के कारण गरीबों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे वंचित वर्गों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं।

कमजोर न्यायिक संस्थाएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप और मानव अधिकार उल्लंघन कानून की सच्चाई पर भारी पड़ते हैं। आम नागरिकों के लिए कानून का वादा और ज़मीनी हकीकत के बीच गहरी खाई बनी रहती है।

सच्चाई यही है कि "न्याय में देरी, न्याय से वंचित करना है।"

कानून तभी सार्थक है जब वह निष्पक्ष, समय पर निर्णय दे और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो। मानव अधिकार केवल किताबों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुरक्षित होने चाहिए।

आह्वान: आइए हम सब मिलकर मज़बूत संस्थाओं, पारदर्शी व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायपालिका की माँग करें ताकि "सबके लिए न्याय" सिर्फ़ संविधान का वादा न रहकर, एक जीता-जागता सच बन सके।

टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत)
tolwaindia@gmail.com

साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू, सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश

भारत की संदिग्ध रजिस्ट्री, जिसे सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, अब देश की साइबर अपराध से लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक बन चुकी है। आइए समझें यह कैसे काम करती है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है:

संदिग्ध रजिस्ट्री क्या है?

इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित किया गया है।

इसका आधार है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से प्राप्त डेटा।

इसमें 14 लाख से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों की पहचान शामिल है, जिनमें अधिकांश वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

यह राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय जांच एजेंसियों, और 61+ बैंक/वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध है।

यह कैसे काम करती है?

रीयल-टाइम निगरानी: बैंक इस रजिस्ट्री का उपयोग ग्राहक की पहचान सत्यापित करने और संदिग्ध खातों में लेनदेन पर नजर रखने के लिए करते हैं।

डेटा साझाकरण: संदिग्ध पहचान बैंक और I4C के बीच साझा की जाती है ताकि धोखेबाजों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोका जा सके।

खाता फ्रीजिंग: धोखाधड़ी से जुड़े खातों को तुरंत फ्रीज़ किया जाता है, अक्सर पैसे निकालने से पहले ही।

वित्तीय सिस्टम से एकीकरण: इसमें निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, वॉलेट्स और भुगतान प्लेटफ़ॉर्म जैसे SBI, Axis Bank, Airtel Payments Bank आदि शामिल हैं।

अब तक का प्रभाव (अगस्त 2025 तक)

मापदंड	आंकड़ा
रोके गए धोखाधड़ी वाले लेनदेन	1.3 लाख+
बचाई गई राशि	₹5,111.80 करोड़
साझा की गई संदिग्ध पहचान	13.06 लाख
फ्रीज़ किए गए खाते	3.54 लाख
ब्लॉक किए गए सिम	7 लाख
चिन्हित किए गए डिवाइस	1.4 लाख

वर्ष 2021–2024 के बीच ₹33,000 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी दर्ज की गई, जिनमें 80% से अधिक मामले वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े थे।

साइबर अपराध रोकथाम में रणनीतिक योगदान

पूर्व-निरोधक ब्लॉकिंग: संदिग्ध तत्वों को पहले ही चिन्हित कर धोखाधड़ी को होने से रोकता है।

एजेंसी समन्वय: पुलिस, बैंक और खुफिया एजेंसियों के बीच निर्बाध सहयोग को सक्षम बनाता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन: निवेश धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी और म्यूल खातों जैसे स्कैम से वित्तीय प्रणाली को मजबूत करता है।

नागरिक सुरक्षा: पीड़ितों को रिफंड दिलाने और हानिकारक ऐप्स, वेबसाइट्स व मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में मदद करता है।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे मजबूत फ़ायरवॉल है।

साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू, सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश

₹31,000 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी कोई आंकड़ा नहीं—यह एक चेतावनी है।

वित्तीय फ्रॉड, डीपफेक और अंतरराष्ट्रीय स्कैम फैक्ट्रियाँ अब किनारे की समस्याएँ नहीं रहीं; ये हमारी डिजिटल विश्वसनीयता को जड़ से हिला रही हैं। सख्त कानून जरूरी हैं, लेकिन नागरिकों की जागरूकता ही पहली फायरवॉल है।

हर स्कैन किया गया QR कोड, हर क्लिक किया गया लिंक, हर जारी किया गया सावधानी की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। साइबर स्वच्छता कोई विकल्प नहीं—यह राष्ट्रीय सुरक्षा है।"

संसदीय स्थायी समिति की 254वीं रिपोर्ट: IT अधिनियम में प्रस्तावित सख्त संशोधन

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन के सुझाव

1. कठोर दंड और गैर-जमानती अपराध

वर्तमान IT अधिनियम में कई साइबर अपराध जमानती हैं और दंड बहुत हल्के हैं।

समिति ने वित्तीय धोखाधड़ी, डीपफेक दुरुपयोग और साइबर स्टॉकिंग जैसे गंभीर अपराधों के लिए सज़ा को कड़ा करने की सिफारिश की है।

2. पीड़ितों को प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अनिवार्य मुआवज़ा

यदि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप जैसे IT मध्यस्थ अवैध सामग्री पर कार्रवाई नहीं करते, तो उन्हें पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा:

वित्तीय नुकसान
मानसिक आघात
प्रतिष्ठा की हानि

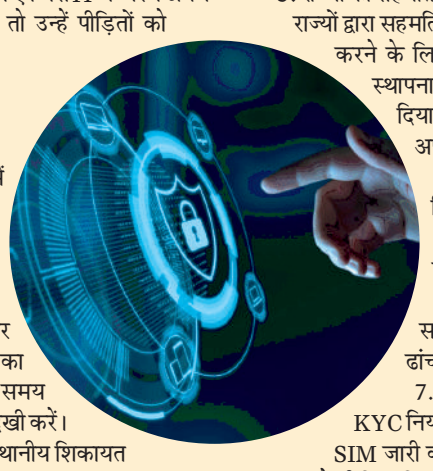

3. सेफ हार्बर नियमों में संशोधन

वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म "सेफ हार्बर" के तहत कानूनी छूट का लाभ उठाते हैं।

समिति ने बार-बार उल्लंघन पर क्रमिक दंड और सेवा निलंबन का प्रस्ताव रखा है, यदि प्लेटफ़ॉर्म तय समय में कंटेंट हटाने के आदेशों की अनदेखी करें।

4. अनिवार्य पंजीकरण और स्थानीय शिकायत अधिकारी

भारत में काम कर रहे सभी IT मध्यस्थों को पंजीकरण करना होगा और नियुक्त करना होगा:

स्थानीय शिकायत अधिकारी
कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए नोडल संपर्क

5. राज्यों की सहमति के बिना CBI को अधिकार

राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने से होने वाली देरी को दूर करने के लिए, समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है ताकि CBI पूरे देश में साइबर अपराधों की जांच कर सके।

6. AI और डीपफेक के लिए नियमन

सभी AI-जनित सामग्री पर वॉटरमार्क अनिवार्य करने की मांग

यूज़र-जनित और AI-जनित सामग्री में अंतर करने के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तावित

7. रियल-टाइम निगरानी और SIM KYC नियम

SIM जारी करने के लिए KYC नियमों को और कड़ा करने की सिफारिश

बैंकों और टेलीकॉम नेटवर्क में रियल-टाइम धोखाधड़ी पहचान प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे मजबूत फायरवॉल है।

चंदन गुप्ता हत्या मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी का फैसला, भारत की जनता के लिए अति विशेष

परिवहन विशेष न्यूज

3 जनवरी, 2025 को, एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (वी.एस. त्रिपाठी) ने 26 जनवरी, 2018 को कासगंज के अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की क्रूर हत्या में मुस्लिम समुदाय के 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह भयानक हत्या चंदन की तिरंगा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी।

आजीवन कारावास की सजा के अलावा, न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और वह है पैसे के लिए किसी का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए महंगे वकीलों की तैयारी! आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर कभी टिप्पणी नहीं की है।

सजा सुनाते समय, न्यायाधीश त्रिपाठी ने दोषियों को बचाने में शामिल राष्ट्रीय और विदेशी एनजीओ की भूमिका पर सवाल उठाए और उन्हें रोकने के लिए अपने आदेश की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी है।

न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा था कि, "इन एनजीओ को कहाँ और कौन फंडिंग कर रहा है, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसकी पूरी तरह से जाँच करने की जरूरत है। ऐसा आरोप है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो ऐसे एनजीओ तुरंत उसका बचाव करने के लिए बहुत महंगे वकील उपलब्ध कराते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है।"

कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित 7 एनजीओ/संगठनों के नाम दिए हैं।

1. सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई
2. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दिल्ली
3. रिहाई मंच
4. अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यू यॉर्क
5. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वाशिंगटन डीसी
6. साउथ एशिया सोलिडेरिटी ग्रुप, लंदन
7. जमीयत उलेमा-ए-हिंद

जस्टिस त्रिपाठी का यह आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है और उन्होंने सरकार से समान मांग की है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की फीस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और उनकी संपत्ति की घोषणा भी सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित की जानी चाहिए। उन्हें हर साल कितना आयकर भरा है, यह भी सार्वजनिक करना चाहिए; वकीलों की फीस केवल चेक/बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही वसूली जानी चाहिए; सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष वकीलों से वकील फीस की प्राप्ति के बारे में शपथ-पत्र मांगा जाना चाहिए कि उनकी फीस किसने चुकाई थी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी आतंकवादी संगठन को फंडिंग तो नहीं दी गई थी।

न्यायाधीश त्रिपाठी के इस ऐतिहासिक आदेश का सभी देशभक्त भारतीयों द्वारा स्वागत और समर्थन होना चाहिए!

रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की मांग करने वाले अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका 2017 से लंबित है।

दो रोहिंग्या, मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर, जो भिखारी जैसे दिखते थे और खराब स्थितियों में रहते थे, उनके लिए छह उच्च-स्तरीय वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ये वकील थे - डॉ. राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉ. अश्विनी कुमार, कोलिन गोंसाल्विस, मयांक फली नरीमन और कपिल सिब्बल।

जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका का 10 महंगे शीर्ष वकील विरोध कर रहे हैं।

पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका का 22 शीर्ष वकील विरोध करते देखे जाते हैं। इनमें सांसद, विधायक और पूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री शामिल हैं।

ऐसे शीर्ष वकीलों के कारण ही यह याचिका लंबे समय से लंबित है।

अक्टूबर 2024 में ही, एक अन्य एनजीओ - सोशल ज्यूरिस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की और केंद्र से रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश देने की अनुमति मांगी।

जब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी कि रोहिंग्या विदेशी हैं और उनके पास देश में प्रवेश की कानूनी अनुमति नहीं है और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो यह एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी।

ऐसे कई वकील और एनजीओ हैं, उन सभी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए।

हमारी निरंकुश और असंवेदनशील न्यायपालिका जवाबदेह बने।

सहदेव पार्क मुल्तान नगर मैं रोहतक रोड पार्क के अंदर एक हफ्ते से ऊपर हो गया है पानी भरा हुआ है और मच्छर पैदा हो रहे हैं इसके अंदर बीमारियों का घर बन रहा है आस पड़ोस के लोग बीमार पड़ रहे हैं प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा कंप्लेंट करने के बावजूद भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है कंप्लेंट दिए हुए भी कृपया करके मीडिया इसको संग्राम में लाएं और आकर यहां पर देखें क्या हालत है धन्यवाद

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.
MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST
transportvisheshcontent@gmail.com Switch account
The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form
* Indicates required question
How you got aware about TOLWA trust *
Social Media
News Paper
Personal connection
Youtube
Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पहली बात हनुमान जी जब संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर लौटते हैं तो भगवान से कहते हैं

प्रभु आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने नहीं भेजा था, बल्कि मेरा भ्रम दूर करने के लिए भेजा था और आज मेरा ये भ्रम टूट गया कि मैं ही आपका राम नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त हूँ

भगवान बोले :- वो कैसे ...? हनुमान जी बोले :- वास्तव में मुझसे भी बड़े भक्त तो भरत जी है, मैं जब संजीवनी लेकर लौट रहा था तब मुझे भरत जी ने बाण मारा और मैं गिरा, तो भरत जी ने, न तो संजीवनी मंगाई, न वैध बुलाया।

कितना भरोसा है उन्हें आपके नाम पर, उन्होंने कहा कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर स्वस्थ हो जाए ।उनके इतना कहते ही मैं उठ बैठा।

सच कितना भरोसा है भरत जी को आपके नाम पर। शिक्षा :- हम भगवान का नाम तो लेते है पर भरोसा नही करते, भरोसा करते भी है तो अपने पुत्रो एवं धन पर, कि बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, धन ही साथ देगा।

उस समय हम भूल जाते है कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे न करे पर भरोसा हम उसी पर करते हैं।

दूसरी बात प्रभु...! बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योकि पर्वत तो आप उठाये हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैं उठाये हुए हूँ। मेरा दूसरा अभिमान भी टूट गया।

शिक्षा :- हमारी भी यही सोच है कि, अपनी गृहस्थी के बोझ को हम ही उठाये हुए हैं। जबकि सत्य यह है कि हमारे नहीं रहने पर भी हमारा परिवार चलता ही है।

इमली के औषधीय गुण और फायदे

वजन कम करना - जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए इमली बेहद फायदेमंद होती है। इमली में मौजूद गुण शरीर के मोटापे को घटाते हैं।

दाद की समस्या - दाद ठीक न हो रहें हो तो इमली के बीजों को नींबू के रस में घिसें और उन्हें दाद वाली जगह पर लगाने से दाद ठीक हो जाते हैं।

पागलपन- बीस ग्राम इमली को पानी के साथ पीस कर इसे छान लें और इस पानी को रोगी को पिलाएं। इससे उन्माद ठीक हो जाता है।

सूजन में इमली - सूजन और जोड़ों में होने वाले दर्द में इमली की पत्तियों को पानी के साथ पीसकर इसके लेप को सूजन वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है।

बवासीर में इमली - खूनी बवासीर की समस्या में इमली का रस सुबह और शाम पीने से राहत मिलती है।

खाज और खुजली में इमली के लाभ - नींबू के रस में इमली के बीजों को अच्छे से पीसें और इसके लेप खाज और खुजली वाली जगह पर लगा दें।

डायबिटीज पर इमली का प्रभाव - इमली ब्लड शूगर के लेवल को बढ़ने से रोकती है। इमली का गूदा रोज खाने से डायबिटीज नियंत्रण में रहती है।

कानों की समस्या - यदि कान में दर्द हो रहा हो तो इमली के रस को तेल में मिलाकर कान में एक.एक बूंद डालें।

अजवायन, दाना मेथी, कलौंजी, सौंफ, अलसी और काले तिल

अजवायन, दाना मेथी, कलौंजी, सौंफ, अलसी और काले तिल के मिश्रण से विटामिन A, B (जैसे B12), B2, E, और C की पूर्ति होती है, साथ ही यह प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, और अन्य खनिज तत्वों का भी अच्छा स्रोत है जो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

विटामिनों की पूर्ति

विटामिन A. कलौंजी में विटामिन A पाया जाता है, जो आँखों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है!

विटामिन B समूह (B2, B12, नियासिन). मेथी और कलौंजी में विटामिन B समूह के विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन), B12 और नियासिन, जो ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक हैं।

विटामिन C. दाना मेथी और कलौंजी में विटामिन C भी होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।

विटामिन E. मेथी में विटामिन E भी पाया जाता है, जो त्वचा और कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

अन्य पोषक तत्व

फाइबर. इस मिश्रण में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारता है, कब्ज दूर करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

प्रोटीन. मेथी, अलसी और काले तिल में प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियों के निर्माण और शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है।

खनिज पदार्थ. इस मिश्रण में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य, रक्त निर्माण और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ज़रूरी हैं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड. अलसी, ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.

यह सभी सामग्री मिलकर एक पौष्टिक मिश्रण बनाती हैं जो शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है।

अतः इन उपरोक्त सभी को मिलाकर रात्रि को सोने से पहले एक चम्मच गुनगुने पानी से लेवें।

प्लास्टिक किसी को न भाये - उसका कचरा सबका दर्द भगाये

चंद्र मोहन

बाजार से खरीदारी करके घर लौटते सभी के हाथों मे छोटे बड़े प्लास्टिक के थैलों को हर कोई आसानी से देखता है. प्यास लगी हो तो पानी की बोतल भी प्लास्टिक की ही बाजार मे उपलब्ध है. रेलगाड़ी मे सफर करो तो स्टेशन पर भी पानी की प्लास्टिक बोतल भी सभी पहचानते हैं.

कुछ भी खाने का सामान मंगवाइये, वह प्लास्टिक के डिब्बे मे ही आता है. सरकार ने भी कई फतवे जारी किए कि प्लास्टिक से दूरी बनायें. लेकिन यह प्लास्टिक है कि हमारी रोज़मरा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

कुछ अरसा पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के महाबलिपुरम में समुन्दर के तट पर न केवल करीब आधे घंटे की सैर की बल्कि वहां सागर तट पर फैले कचरे को भी उठा कर स्वच्छ्ता का सन्देश दिया. पी एम मोदी ने एक तीन मिनट का वीडियो भी शेयर किया कि वहां घूमते हुए प्लास्टिक की बोतलें और अन्य प्लास्टिक के सामान को उठाया और होटल कर्मचारी को साफ सफाई का ध्यान रखने का सन्देश भी सुना दिया.

प्लास्टिक कितना खतरनाक हो सकता है, इसको सभी जानते हैं लेकिन उससे छुटकारा पाया जाये, इसको कैसे समझा जाये!

प्लास्टिक से पैरासिटामोल:

वैज्ञानिकों ने २४ घंटे में कचरे को दर्द निवारक में बदल दिया .एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके पीईटी प्लास्टिक कचरे को पैरासिटामोल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विकसित की है।व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन शुरू करने से पहले इसमें और विकास की आवश्यकता है।

यू.के. में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के नए शोध ने पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) प्लास्टिक के अणुओं को एसिटामिनोफेन में बदलने के लिए एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है जिसे आम तौर पर पैरासिटामोल के रूप में जाना जाता है। यह प्लास्टिक प्रदूषण और दवा निर्माण में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता दोनों को संबोधित करने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

एसिटामिनोफेन का उत्पादन आमतौर पर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके किया जाता है। प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट उत्पादों के साथ इन अवयवों को प्रतिस्थापित करने से दो प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का अभिनव समाधान मिल सकता है।

यद्यपि इस प्रक्रिया को बढ़ाने तथा इसकी औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने में समय लगेगा, फिर भी इस नई प्रौद्योगिकी में टिकाऊ औषधि उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काफी संभावनाएं हैं।

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा जारी समाचार के अनुसार इस प्रक्रिया के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं:

त्वरित परिणाम: परिणाम २४ घंटे के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं।

कॉम्पैक्ट सेटअप: इसे एक छोटी प्रयोगशाला सेटिंग में किया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता: यह कमरे के तापमान पर संचालित होता है जिससे अत्यधिक गर्म या ठंडा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकीविद् स्टीफन वालेस कहते हैं, "यह कार्य दर्शाता है कि पीईटी प्लास्टिक केवल अपशिष्ट या प्लास्टिक बनने वाला पदार्थ नहीं है - इसे सूक्ष्मजीवों द्वारा मूल्यवान नए उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है जिनमें रोगों के उपचार की क्षमता भी शामिल है।"

विशेषज्ञों का कहना है कि यह नया दृष्टिकोण दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग जीव विज्ञान के साथ मिलकर जीवित सूक्ष्मजीवी कारखानों का निर्माण कर सकता है, जो टिकाऊ रसायनों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, साथ ही अपशिष्ट, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करेंगे।

नेचर केमिस्ट्री में प्रकाशित इस शोध को ईपीएसआरसी केस पुरस्कार और बायोफार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा वित्त पोषित किया गया था तथा एडिनबर्ग इनोवेशन (ईआई) द्वारा समर्थित किया गया था।

ईआई में कंसल्टेंसी के प्रमुख इयान हैच ने कहा, "हम इन अत्याधुनिक खोजों को विश्व-परिवर्तनकारी नवाचारों में बदलने के लिए स्टीफन और विश्वविद्यालय के अन्य लोगों के साथ काम करने के लिए एस्ट्राजेनेका जैसी असाधारण कंपनियों को ला रहे हैं। इंजीनियरिंग जीवविज्ञान जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को खत्म करने, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करने और टिकाऊ रसायन और सामग्री बनाने की अपार संभावनाएं प्रदान करता है और हम संभावित सहयोगियों को संपर्क करने के लिए आमंत्रित करेंगे"

सब ने अब तक यही सोचा था कि कांच की बोतलें ही सबसे बढ़िया ऑप्शन हैं, है ना? हमने उन्हें ईको फ्रेंडली माना, सेहत के लिए बेहतर समझा और अपने किचन में भी जगह दी लेकिन हाल ही में फ्रांस की फूड सेफ्टी एजेंसी ANSES द्वारा किए गए एक नए शोध ने हमारे इस भरोसे की नींव हिला दी है।

जी हां, यह स्टडी एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाती है, जिसे पढ़कर आप शायद अपनी कांच की बोतल को फेंकने पर मजबूर हो जाएं। अध्ययन बताता है कि आपकी पसंदीदा कांच की बोतलें प्लास्टिक से कहीं ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक कणों से दूषित हो सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।

स्टडी में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे

वैज्ञानिकों को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने अपने शुरुआती नतीजे देखे। उन्हें उम्मीद थी कि कांच की बोतलें प्लास्टिक की तुलना में साफ होंगी लेकिन हुआ ठीक उलटा! इस अध्ययन में पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, आइस टी और बीयर जैसी चीजों की कांच की बोतलों में प्रति लीटर औसतन 100 माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए। यह संख्या प्लास्टिक या धातु के डिब्बों में पाए जाने वाले कणों से 50 गुना ज्यादा थी।

कहीं ढक्कन ही तो नहीं गुनहगार?

शोधकर्ताओं को लगा कि इस गंदगी का मुख्य कारण बोतल के ढक्कन हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि बोतलों में पाए गए ज्यादातर प्लास्टिक कणों का रंग और बनावट ढक्कन के बाहरी पेंट से मिलती-जुलती थी। इसका मतलब है कि कांच की बोतलों को बंद करने वाले धातु के ढक्कनों के बाहरी पेंट से ही ये छोटे-छोटे प्लास्टिक कण ड्रिंक्स में मिल रहे थे।

"Diabetes का खतरा बढ़ाती है प्लास्टिक वॉटर बोतल, जानें कैसे करें सुरक्षित Plastic की पहचान

प्लास्टिक इन दिनों कई तरीकों से इस्तेमाल होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल वॉटर बोतल की तरह किया जाता है। हालांकि Plastic Water Bottle के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में तो सभी जानते हैं। इसी बीच अब इसे लेकर एक ताजा स्टडी सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि प्लास्टिक बोतल के इस्तेमाल से Diabetes का खतरा बढ़ सकता है।

डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है प्लास्टिक बोतल

प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है।

लोग आमतौर इसे बोतल में रूप में इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, हाल ही में पता चला है कि इससे Diabetes का खतरा बढ़ता है।

प्लास्टिक इन दिनों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम आमतौर पर कई तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। खासकर बोतल के रूप में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग अक्सर पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से काफी नुकसान होता है। यह कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। इसी बीच अब इसे लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है।

हाल ही में आई इस स्टडी में पता चला कि प्लास्टिक की पानी की बोतल का इस्तेमाल करने से डायबिटीज और हार्मोन डिसरप्शन का खतरा बढ़ता है।

आइए विस्तार में जानते हैं क्या कहती है स्टडी-डायबिटीज

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के एक अध्ययन से पता चला कि प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला BPA इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है जिससे संभावित रूप से टाइप २ डायबिटीज का

एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोध के मुख्य लेखक प्रोफेसर स्टीफन वालेस ने कहा, "अभी तक लोगों को यह एहसास नहीं है कि पैरासिटामोल तेल से बनता है।" "यह तकनीक दिखाती है कि पहली बार इस तरह से रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर हम पैरासिटामोल को अधिक टिकाऊ तरीके से बना सकते हैं और साथ ही पर्यावरण से प्लास्टिक कचरे को भी साफ कर सकते हैं।"

नेचर केमिस्ट्री नामक पत्रिका में लिखते हुए वालेस और उनके साथियों ने बताया कि कैसे उन्होंने पाया कि लॉसन रीअरेंजमेंट नामक एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया जो प्रकृति में पहले कभी नहीं देखी गई, जैव-संगत थी। दूसरे शब्दों में, इसे जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति में उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना किया जा सकता है।

विश्व साक्षरता दिवस आज

किसी भी देश की खुशहाली और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां रहने वाले लोग कितने पढ़े-लिखें हैं। ऐसे में लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में भी इसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान इसका एक उदाहरण है।

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस

==================

जिस भी देश में जितने ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस देश का भविष्य और परिवेश उतना ही बेहतर होगा। साक्षरता शब्द साक्षर से आता है, जिसका अर्थ होता है - शिक्षित होना। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य दुनियाभर की आबादी को साक्षर बनाने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करें।

कैसे हुई इस दिन की शुरूआत?

==========================

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जड़ें 1965 में ईरान के तेहरान में आयोजित निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन से जुड़ी हैं। इस सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के विचार को जन्म दिया। इसके बाद, यूनेस्को ने 1966 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया।

एक साल बाद, 8 सितंबर, 1967 को, दुनिया ने पहली बार इस खास दिन को मनाया, जिसने एक महत्वपूर्ण वैश्विक पालन की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक हर साल नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।

भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष रिपोर्ट

नई दिल्ली, संजय साग़र सिंह - भारत-रूस रिलेशन पर विशेष रिपोर्ट। भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। इसी क्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप की भारत-विरोधी टिप्पणियों पर कड़ा जवाब दिया, बल्कि भारत के लिए रूस के दरवाजे खोलते हुए 10 लाख भारतीयों को रोजगार देने की योजना का ऐलान भी किया है। लेक़नि भारत और रूस के बीच की नजदीकी पाकिस्तानी चश्मा पहने ट्रंप को अब हजम नहीं हो रही है। ट्रंप की धमकियों के बाद रूस भारत के साथ अपने व्यापार को और भी मजबूत करना चाहता है। इसलिए रूस की योजना है कि वह साल 2025 के अंत तक भारत से करीब 10 लाख मजदूर बुलाएगा, जो उसके अलग-अलग शहरों और इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस योजना को आसान बनाने के लिए रूस भारत में एक नई व्यवस्था बना रहा है ताकि वीजा और दस्तावेजों का काम भी जल्दी निपट सके। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत के लोग उनके यहां काम में शामिल हों। भारतीयों को अच्छी सैलरी दी जायेगी।

रूस बन सकता है भारतीय कामगारों का अगला बड़ा गंतव्य

जहाँ एक ओर अमेरिका और यूरोप में वीजा प्रतिबंधों और संरक्षणवाद की नीति के चलते अवसर सीमित हो रहे हैं, वहीं रूस ने भारतीय श्रमिकों के लिए नई राह खोली है। यह न केवल भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि भारत के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक रूप से स्थिर भविष्य का द्वार भी खोल सकता है।

भारत से रिश्ते मजबूत करेंगे, धौंस नहीं चलने देंगेः - पुतिन

हाल ही में चीन में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद, रूस ने भारत के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक और नई दिशा देने के संकेत दिए हैं। ट्रंप की 'प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी' की आलोचना करते हुए पुतिन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी "भारत से हमारा रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। हम पर धौंस नहीं चलेगी।"

रूस में 10 लाख भारतीय कामगारों की ज़रूरत, कंपनियों ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया

रूस की कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ - विशेषकर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और धातु उत्पादन क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी देखी जा रही है। इसी के मद्देनज़र रूस ने 2025 के अंत तक भारत से 10 लाख कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों की भर्ती करने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल स्वेर्दलोव्स्क, येकातेरिनबर्ग और कैलिनिनग्राद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीयों की प्राथमिक नियुक्ति की जा रही है।

सुझाव: रूसी भाषा सीखें, भविष्य बनाएं -

भारतीय जानकारों ने युवाओं को सलाह दी है कि वे रूसी भाषा सीखें ताकि वे वहां बेहतर तरीके से काम कर सकें और लंबी अवधि तक वहां टिक सकें। उन्होंने कहा, "रूस में काम करने के लिए भाषा का ज्ञान जरूरी है। हमारी इंडस्ट्री भारतीय कौशल की कद्र करती है। रूसी कंपनियां भी इस दिशा में सक्रिय हैं और भारत में प्रशिक्षण केंद्रों व भाषा शिक्षण शिविरों की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं।ः

रोजगार से पहले तैयार रहें भारतीय, मौसम और भाषा बनी रहेंगी चुनौती

रूस की जलवायु और संस्कृति भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। वहाँ सर्दियों में तापमान -15 से -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रूसी भोजन शैली और भाषा भी एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। इसके अलावा, खाने-पीने की आदतें और भाषा भी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रूस में ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और वहां शाकाहारी खाना भी कम ही मिलता है। जाने से पहले हर व्यक्ति को प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए क्युकी भाषा, मांसाहारी खानपान और सर्द मौसम सब कुछ अलग होगा लेकिन अगर सही तैयारी के साथ कोई जाता है, तो ये एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का बड़ा मौका बन सकता है। रूस में मिलने वाली सैलरी भारत की तुलना में काफ़ी बेहतर हैं और इससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। हालांकि, रूसी कंपनियों ने वादा किया है कि वे भारतीय कर्मचारियों को गरम कपड़े, आवास और उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराएंगी ताकि भारतीयों को कोई खास तकलीफ न हो।

दूतावास तैयार, राजनयिक तंत्र सक्रिय

रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने बताया कि भारतीय कामगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रूस में भारत एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की तैयारी कर रहा है, ताकि वीज़ा, पासपोर्ट और कांसुलर सेवाएं बेहतर ढंग से दी जा सकें। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मांगः कंस्ट्रक्शन वर्क, हेवी मशीन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, मेटल फैब्रिकेशन, फिश प्रॉसेसिंग यूनिट्स आदि।

मौका बड़ा है, पर तैयारी भी ज़रूरी है

रूसी सरकार भारतीय मजदूरों की सुविधा के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। भारत में ही वर्क वीज़ा, भाषा प्रशिक्षण और इंडक्शन प्रोग्राम शुरू करने की योजना है ताकि रूस पहुंचने से पहले ही श्रमिकों को वहां की कार्य संस्कृति, मशीनों और कानूनों की जानकारी दी जा सके।

क्या है वीजा प्रक्रिया?

रूस में नौकरी पाने के लिए भारतीयों को पहले किसी कंपनी से जॉब ऑफर प्राप्त करना होगा, जिसके आधार पर वर्क वीजा जारी किया जाएगा। स्किल्ड वर्कर्स को 'हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट (HQS)' वीजा दिया जाएगा, जो अधिक सुविधाएं और वेतनमान प्रदान करता है। रूस भारतीयों के हुनर की कद्र रूस करता हैं, रूस की बड़ी-बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत से लोग आए और काम करे। बीते साल 2024 में जब कैलिनिनग्राद फिश प्रॉसेसिंग कॉम्प्लेक्स 'Za Rodinu' में श्रमिकों की कमी हुई थी, तब भी भारत से लोग को बुलाया था और अच्छी सैलरी भी दी गयी थी।

कैंप लगाकर मजदूरों की जाएगी भर्ती

इस योजना की शुरुआत हो भी चुकी है, कुछ भारतीय मजदूरों ने रूस में जाकर काम शुरू कर दिया है। मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगहों पर भारतीय मजदूरों का पहला बैच भेजा गया है और वहां उन्हें शुरुआती ट्रेनिंग भी दी गई है। लगभग 4,000 भारतीयों ने आवेदन किया हुआ था और कुछ कलिनिनग्राद में काम भी शुरू हुआ है। रूस में बहुत सारी कंपनियां अब भारत में कैंप लगाकर मजदूरों की भर्ती कर रही हैं। आने वाले समय में भारत और रूस के बीच एक खास समझौता होगा, जिसके तहत भारत में ही मजदूरों को रूसी भाषा और मशीनों से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो काम शुरू करने के पहले से ही पूरी तरह तैयार रहें। भारत के लिए ये मौका रोजगार के लिहाज़ से काफी अहम माना जा रहा है। खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी काम जानते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कर सकते हैं। इससे भारतीय मजदूरों को रूस के उद्योगों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सकेगा, ताकि उनकी भाषा और काम की आदतों में मेल खा सके।

फिल्म समीक्षा : अतीत के पन्नों को पलटती - 'द बंगाल फाइल्स'

"ताशकंद फाइल्स" और "कश्मीर फाइल्स" के बाद विवेक अग्निहोत्री ने बंगाल की फाइल्स ओपन की हैं। विवादास्पद इसमें कुछ भी नहीं हैं। भारती बैनर्जी के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन के कालखंड से अब तक दर्द सह रही नारी का प्रतिबिम्ब बन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी रेखांकित करती हैं।

कहानी - वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक दलित लड़की के गायब होने की तफ्तीश के लिए दिल्ली से सी.बी.आई. अफसर शिवा पंडित आता है। शक स्थानीय विधायक सरदार हुसैनी पर है। शिवा पर हमला होता है क्योंकि इलाके में पुलिस नहीं विधायक की चलती है। वो सीमा पार से अवैध लोगों को बसाता हैं।उन्हें यहां का नागरिक बना इलाके की डेमोग्राफी चेंज कर हिन्दू-मुसलमान बना रहा है। ताकि उसकी हुकूमत चलती रहे। तफ्तीश के दौरान शिवा को आज़ादी की लड़ाई लड़ चुकी भारती बैनर्जी मिलती है। जिसने अगस्त 1946 के बंगाल का 'डायरेक्ट एक्शन डे' देखा था।जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, नोआखाली के दंगे देखे।आज भी बीते दिनों की उन भयानक यादों में वो खो जाती है। शिवा पाता है कि हालात आज भी कमोबेश वैसे ही हैं। हुक्मरान आज भी अपने स्वार्थ के लिए 'वी द पीपल' को इस्तेमाल कर रहे हैं।

निर्देशन, गीत-संगीत - विवेक अग्निहोत्री की राइटिंग और रिसर्च बढ़िया है, ये उनके मीडिया में आ रहे इंटरव्यूज़ से भी समझा जा सकता है। अतीत में हमारे कर्णधारों द्वारा की गईं भूलों को तथ्यों के साथ रेखांकित करती है। सवाल ये हैं कि वे रिसर्च इतनी अधिकता में की हैं वो दो फिल्मों में समा जाती। इसलिए भी फ़ल्मि लंबी हो गई हैं। बेहतर होता है इसे दो पार्ट में बनाते और कहानी उस जगह छोड़ते जिससे दर्शकों में इंटरेस्ट पैदा होता। फिल्म कहीं-कहीं बोझिल होने लगती हैं, दर्शक इंतजार करता है कि फिल्म कब खत्म होगी। साथ ही कंफ्यूज भी होता रहता है कि फिल्म वर्तमान में है या अतीत में। निर्देशक ने कई सीन तो इतने प्रभावी बनाए हैं कि आप पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। जैसे-महिलाओं को हैंगर से लटकाना, दो मोटरसाइकलों से सरदार बने अमर के दो टुकड़े हो जाना, जज की सरेआम बेईज्जती, नमाशी द्वारा बच्चे को गोली मारना व काकू की गर्दन काटना, हुसैनी द्वारा शिवा को बच्चे के सामने सॉरी बुलवाना, अमर व भारती का लाशों को ढोना, गिद्धों का लाशों पर मंडराना, पानी नहीं होने पर पसीना पीते हुए दिखाना और बच्चे का सड़क पे पड़ी रोटी खाना। ये दिखता है कि उनके निर्देशन में कितनी गहराई है। जिसे सिनेमाटोग्राफर अत्तर सिंह सैनी ने कैमरे में ज़बरदस्त कैद किया हैं। फ़ल्मि के संगीतकार रोहित शर्मा ने संगीत अच्छा दिया हैं। क्लाइमैक्स ज्यादा प्रभावी नहीं बन पाया हैं।

अभिनय - अफसरों की सुने या ईमानदारी से काम करे। इस कश्मकश में फसें एक सीबीआई अफसर के रोल में दर्शन कुमार ने इम्प्रेस किया है।

गदर-2 के बाद सिमरत कौर रंधावा ने पल्लवी जोशी के जवानी वाले किरदार में कमाल किया हैं। उनके चेहरे के आते-जाते हाव-भाव और लंबे संवादों की निरंतरता काबिले तारीफ हैं। पल्लवी जोशी की चुप्पी कमाल हैं, वे आँखो से बहुत कुछ बोल जाती हैं। क्लायमेक्स में व्यथा बयां कर वे दर्शकों के आँसू निकलवा लेती हैं। अमर बने एकलव्य सूद ने एक सिख के किरदार में जान डाल दी हैं। अनुपम खेर ने महात्मा गांधी के रोल को बखूबी जिया हैं। हुसैनी बने शाश्वत चटर्जी और नमाशी चक्रवर्ती अपने किरदारों में जबरदस्त क्रूरता का परिचय देते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का रोल छोटा होने के बावजूद वे प्रभावी रहें। राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, सौरव दास ने भी उम्दा काम किया हैं।

खूबियाँ - कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक बेहतरीन फिल्म पेश की है। उनका लेखन और निर्देशन असर छोड़ता है। थिएटर में जाकर ही आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कलाकारों का दिल छूने वाला अभिनय इसका प्लस पॉइंट हैं। इसमें रियलिटी कूट-कूट कर भरी है, इसके लिए कला निर्देशक बधाई के पात्र हैं।

कमजोरी - इसकी तीन घंटे 24 मिनट की लम्बाई सबसे बड़ी बाधा हैं। एडिटर शंख राजाध्यक्ष लगभग 25 मिनट कम कर सकते थे। रियलिटी का डोज़ ओवरलोड हैं। साउथ की मूवीज के एक्शन दृश्य आराम से झेलनेवालों को कोई परेशानी नहीं होगी। कमजोर दिल वालों को यह फिल्म परेशान कर सकती है।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

पदमपुर "वास्तु विहार" के आपार्टमेंट पर विवाद शुरू, बिल्डर पर गंभीर आरोप ,खरीदारों में आक्रोश

ओरेरा व अन्य जरूरी राजस्व नियमों को दरकिनार करने में सुंदरगढ़ अव्वल- डॉ राजकुमार यादव

राउरकेला: कुआरमुंडा क्षेत्र के रपदमपुर वास्तु विहारर के अपार्टमेंट में फ्लैट खरीददारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए खरीददारों का कहना है कि उन्होंने पैसे का भुगतान करने के बावजूद अब तक फ्लैट का कागजात नहीं मिला।दस्तावेज़ मांगने पर न सिर्फ टालमटोल किया जा रहा है, बल्कि रविवार को मारपीट और अभद्र व्यवहार तक की नौबत आ गई।

इस मामले में वास्तु विहार के स्थानीय प्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है,जिसने फ्लेट बेचने के वर्षो बाद भी दस्तावेज नही दिया है और उस पर से रविवार को मार पीट भी की।

फ्लैट खरीददार विकास प्रसाद ने रविवार को कुआरमुंडा आउटपोस्ट में एफआईआर दर्ज कराई है।उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार को जब वे अन्य ग्राहकों के साथ कागजात लेने पहुचे, तो बिल्डर के लोगों ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। मौके पर मौजूद अन्य पीड़ित ग्राहकों, जिनमें दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल थे, ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना है कि वर्षों से किस्तों में रकम जमा करने के बावजूद बिल्डर ने दस्तावेज़ देने से साफ़ इनकार कर दिया है। कुछ महिला खरीदारों ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया।

वहीं वास्तु विहार मैनेजमेंट ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि जिन ग्राहकों की विभिन्न प्रत्याशीत अप्रत्याशीत राशि अब तक बकाया है, केवल उनके दस्तावेज़ रोके गए हैं व आधिकारिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को ही सौपे जाएंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि पूर्ण भुगतान करने वाले खरीदारों को दस्तावेज़ दिए जा रहे हैं और इस पूरे विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है।

कुआरमुंडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जाच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जाँच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि आरोपी सही हैं या मैनेजमेंट का पक्ष मजबूत है।

इस घटना के बाद इलाके में खरीदारों में भारी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि बिल्डर की मनमानी से उनका विश्वास टूट गया है और अब वे प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव के अनुसार पहले भी प्रकाशित खबरों में उड़ीसा में ही नहीं विशेष रूप से सुंदरगढ़ में ओरेरा के नियमों का उल्लंघन ही नहीं माखोंल उड़ाया जा रहा है।प्लाटिंग के नाम पर लोगों से बेवजह अनगिनत रुपए वसूली लेने के बावजूद भी उन्हें उचित कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। दंडियापाली, कलूंगा व ब्राह्मनीतरंग में किसी के जमीन पर कोई ओर ही घर बना कर बैठे हैं, जमीन किसी की पट्टा किसीका, रेवेन्यू अपील, आरपी केस के नाम पर तत्कालीन बीजद सरकार में जारी लूट अब तक बंद नहीं हुई है एनडीए नेतृत्व वाली स्थानीय प्रशासन को इस ओर उचित कदम उठाने की परम आवश्यकता है विशेष रूप से तत्कालीन बीजू जनता दल की सरकार ने बिना सोचे समझे बिना नक्शे के, बिना किसी गाइडलाइन के ही कई सौ एकड़ को ऐसे ही प्लाटिंग कटते व विभिन्न स्किमों के नाम पर बटते देखा। जिससे कि आने वाले समय में कुँआरमुण्डा, राउरकेला, लाठीकाटा, बिसरा, रमेगा प्लाटिंगर, हाईराइज लाइफस्टाइल और न जाने विभिन्न तरह से लोग बिना ओरेरा के अप्रूवल के ही नक्शे के बिना ही प्लॉट पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। फ्लैट्स व हाउसिंग प्रोजेक्टस का भी यही हाल है और प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ मौन समर्थन किये जा रहा है। एनडीए सरकार के मुखिया मोहन माझी स्वच्छता सह नियम एवं पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने की मंशा लिए हुए जीस तेज गति से कार्य कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि इस तरह की प्रक्रिया ज्यादा दिन चल पाएगी। भू माफिया का कब्जा व तंत्र इतना मजबूत है की पंजीयन कार्यालय से लेकर तहसील तक यह लोग लॉबी करके खुद के लोग बैठा रहे हैं, सूत्रों के अनुसार भूमाफिया गण के सिण्डिकेट ने तीन कर्मचारियों के तिकड़ी को मुख्यालय में बैठा रखा है जो इनका ख्याल रखते है व नियमों को नजरअंदाज भी करते हुए इनके लिए ढाल का काम करते हैं। इसकी भी जांच होनी जरूरी है। इनके साहस की पराकाष्ठा को नापने का यह बेहतर पैमाना है की सुंदरगढ़ जिले में विभिन्न एजेंसीयों के द्वारा - विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जब्त की गई जमीन न जाने कैसे और कब सरकारी कब्जे से हटकर उनके पट्टे (आर ओ आर) तक बदल दिए गए हैं व भूलेख में परिलक्षित है, इनकी भी उच्चस्तरीय एवं गहन जांच की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ढीलाई बरती गई होगी तभी आज वास्तु विहार का जो मामला है सामने आया है कई वर्षों से लंबीत किया गया प्रोजेक्ट आज भी हैंडोवर को तैयार नहीं है इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। सुंदरगढ़ जिले में जमीनों को लेकर विभागीय अधिकारीयों पर क्रिमिनल केसेस व विजिलेंस केसेस की कमी नहीं है दर्जनों आर आई (रेवेन्यू इंस्पेक्टर) है जिनके नाम पर विजिलेंस में लंबित मामले अभी भी हैं।

वहीं वास्तु विहार के मैनेजमेंट को पूछे जाने पर उन्होंने तकनीकी बातों का हवाला दिया जैसे किन्हीं के कुछ पैसे बाकी है फेसिंग को लेकर व अन्य बातों को लेकर कुछ मामूली मूल्य में विवाद है या अन्य बातों को लेकर मैनेजमेंट से जो भी नाराजगी है उसे सामने बैठकर सुलझाया जा सकता है किंतु गलत तरीके से वाद विवाद बढ़ने से वास्तु विहार जैसी बड़ी कंपनी जिन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडोवर किए हैं यह फ़ाइल खोलकर देखना पड़ता है उसके ऊपर लगाए गए यह सभी आरोप बेबुनियाद है व कंपनी कानूनी रूप से व अन्य जरूरी बैठक के द्वारा निपटाने का प्रयास जरूर करेगी वास्तु विहार के लिए अभी तो यह शुरुआत है, मंजिल कहीं और है वास्तु विहार की टीम को अपने कार्य कुशलता पर पूरा भरोसा है व आगे भी न जाने कितने प्रोजेक्टस आने बाकी है यह समय बताएगा। खैर पुलिस के रिपोर्ट का इंतजार है आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो ग्राहक पैसे लगा चुके हैं उन्हें इसका भुगतान तो भरना होगा लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से इसे रोका जा सकता था यह समझने वाली बात है।

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है–
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
● पुराने कपड़े
● पुराने कंबल
● पुराने जूते-चप्पल
● बच्चों के लिए बैग
● किताबें
आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
● दशहरे के दूसरे दिन
● दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
● स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

दिल्ली पुलिस ने 400 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद किए। 101 फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए

स्वतंत्र सिंह नई दिल्ली

मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, गृह मंत्रालय (MHA) और दूरसंचार विभाग (DoT) ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे जाँच एजेंसियों और आम जनता, दोनों ही दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करके चोरी या स्नैच किए गए मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। इससे चोरों और स्नैचरों के पास इन फ़ोनों को भारत से बाहर तस्करी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दक्षिण जिले की टीमों ने जेबकतरों, लुटेरों, स्नैचरों और रिसीवर्स से चोरी और खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद करने और उन्हें उनके मालिकों को वापस करने में सराहनीय काम किया है। पिछले दो महीनों में, स्पेशल स्टाफ की टीम ने लगभग 200 मोबाइल फ़ोन, एएटीएस की टीम ने लगभग 50 मोबाइल फ़ोन, नेब सराय पुलिस स्टेशन की टीम ने लगभग 100 मोबाइल फ़ोन और ज़िले की अन्य टीमों ने भी लगभग 100 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं।

काफी प्रयासों के बाद, टीमों ने उनके मालिकों का पता लगाया और आज पहली खेप में, पिछले दो महीनों में पुलिस द्वारा विभिन्न अभियानों में बरामद किए गए 101 मोबाइल फ़ोन, डीसीपी कार्यालय में आयोजित एक छोटे से समारोह में उनके मालिकों को लौटा दिए गए। दक्षिण ज़िले की विभिन्न टीमों के समर्पित संयुक्त प्रयासों से न केवल पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि पुलिस का मनोबल भी बढ़ेगा।

बरामद किए गए 101 मोबाइल फ़ोनों का विवरण (संबंधित पुलिस थानों द्वारा बरामद) अंबेडकर नगर थाना – 14, डिफेंस कॉलोनी थाना – 11, फतेहपुर बेरी थाना – 7, ग्रेटर कैलाश थाना – 5, हौज़ खास थाना – 4, कोटला मुबारकपुर थाना – 7, लोधी कॉलोनी थाना – 3, मैदान गढ़ी थाना – 3, महरौली थाना – 5, नेब सराय थाना – 11, संगम विहार थाना – 16, साकेत थाना – 5, तिगरी थाना – 10

स्वामित्व स्थापित होने के बाद शेष फ़ोनों को उनके मालिकों को लौटाने के लिए शीघ्र ही एक और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह तमाम जानकारियां

अंकित चौहान, पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला, नई दिल्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

दो दिवसीय फोटो एग्ज़िबिशन एवं प्रतियोगिता का सफल समापन

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, मीडिया फोटो जर्नलिस्ट ट्रस्ट ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सहयोग से दो दिवसीय फोटो एग्ज़िबिशन एवं प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया, जिसका सफल समापन आज हुआ। इस आयोजन में राष्ट्रीय मीडिया के 25 प्रख्यात फोटो जर्नलिस्टों ने भाग लिया और अपनी उत्कृष्ट कृतियों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन एवं शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे विशिष्ट गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। इनमें प्रमुख रूप से –आकाश कुमार (संस्थापक, बीइंग हार्ट फाउंडेशन), मनोज जैन (निगम पार्षद), विपिन गोयल (बीजेपी सदस्य), डॉ. संजय सोलंकी (सर गंगा राम अस्पताल), निशी सिंह (संस्थापक, नाद फाउंडेशन), नित्यानंद तिवारी (सिंगर,), शैलेश गिरी (फिल्म पी .आर. ओ), परमजीत सिंह पम्मा, नीरज ठाकुर (सेक्रेटरी जनरल), अभय सोपोरी (प्रसिद्ध संतूर वादक), रागिनी रेनू (सूफी गायिका), डॉ. धीरेन्द्र कुबेर (आरएमएल अस्पताल), दीपक तंवर (पूर्व प्रत्याशी, देवली विधान सभा), जी. सतेंद्र त्रिपाठी, रविन्द्र कुमार (एग्जीक्यूटिव मेंबर, पीसीआई), डॉ. आमना मिर्ज़ा आदि शामिल रहे।

इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष नवल हंस के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारी – कमर सिब्तेन, विजय वर्मा, वसीम सरवर, हेमन्त रावत, जगजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह और कनन सरन भी उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता का मूल्यांकन ज्यूरी मेम्बर्स – कमलजीत सिंह, सुनील मल्होत्रा, शंकर चक्रवर्ती और जी.एन. झा – द्वारा किया गया। विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कृत किया गया –प्रथम पुरस्कार : मानवेन्द्र वशिष्ठ (पीटीआई), द्वितीय पुरस्कार : मुकेश अग्रवाल (ट्रिब्यून), तृतीय पुरस्कार : विवेक निगम (अमर उजाला)

इसके अतिरिक्त पाँच फोटो जर्नलिस्टों – इम्तियाज खान, मिहिर सिंह, धुर्व कुमार, नीरज कोली और सुमित पाल – को कंसोलेशन प्राइज़ प्रदान किए गए। सभी विजेताओं को पुरस्कार एवं सम्मान मनोज कुमार जैन (निगम पार्षद) द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने कहा कि ऐसे सार्थक आयोजनों से न केवल कला और पत्रकारिता को बढ़ावा मिलता है बल्कि समाज में सकारात्मकता और जागरूकता का संचार भी होता है।

लालकिला मैदान पर फिल्मी सितारों से सजेगी भव्य लव कुश रामलीला

मुख्य संवाददाता

विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता कान्सीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित की गयी। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए लीला कमेटी के प्रेसीडेन्ट अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मंचन 22 सितम्बर से 03 अक्तूबर 2025 तक होगा एवं दशहरा पर्व 02 अक्तूबर 2025 को पूरे विश्व में धूम-धाम से मनाया जायेगा ।

अर्जुन कुमार ने मीडिया के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि इस वर्ष की रामलीला कई मायनों में ऐतिहासिक, अद्भुत और भव्य होगी। देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को मंच पर जीवंत करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार ओर परम्पराओं का संगम मंच पर देखने को मिलेगा। इस बार बालिवुड के 15 नामचीन स्टार्स के साथ-साथ टीवी ओर रंगमंच 140 कलाकार विभिन्न किरदारों में नजर आयेंगे।

अर्जुन कुमार ने यह भी बताया कि इस बार रामलीला मंचन बहुत दिव्य होगा । मंच पर मौजदू रामलीला में श्री राम, सीता जी और हनुमान जी का किरदार निभा रहें मुंबई नामचीन फिल्मस्टार किंशुक वैध, रिनी आर्या ओर मल्हार पांड्या का परिचय कराया। किंयुक वैध ने अनेकों फिल्मों एवं टीवी सीरियल में अभिनय किया है कर्ण संगिनी में अर्जुन, शाका लाका बूम-बूम संजू, विष्णु पुराण में प्रहलाद में प्रखुम भूमिका निभाई। फिल्म एक्ट्रर्स, एंकर, माडल रिनी आर्या ने प्रसिद्ध टीवी सीरियल सुवरीन मुग्गल टापर आफ द इयर, कुल्फी कुमार बाजेवाला, पौराणिक धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में माता लक्ष्मी जी की अहम भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी अभिनेता मल्हार पांड्या पौराणिक एवं ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाते है टीवी सीरियल राधाकृष्ण में कृष्ण, वीर हनुमान में सूर्य देव सहित टीवी ओटी 'प्लेट फार्म पर दिखाये जा रहे अनेको सीरियलर्स में प्रखुख निभा रहे है।

लव कुश रामलीला कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा इस वर्ष लीला कमेटी का पूरा ध्यान लीला मंचन को अति आधुनिक नई तकनीक, ए-आई, डिजिटल, हाईटेक, 3डी मेपिंग, विजुअल इफेक्ट, 8 ट्रेक साउथ सिस्टम 2 के माध्यम प्रस्तुत किया जायेगा। विभिन्न टीवी चैनल, यू-ट्यूब के 150 से अधिक चैनलों के माध्यम से इस बार देश विदेश के 25 करोड़ से ज्यादा दर्शक रामलीला लाईव मंचन देखेंगे। सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार फिल्म स्टार्स के कास्टयूम बहुत ही सुन्दर एवं भव्य तैयार किए जा रहें। रामभक्तों के लिए पंडाल को तैयार करने के लिए कलकता, मथुरा, वृदांवन, उज्जैन आदि के कारीगरों द्वारा महीनों की कड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। पंडाल की भव्यता, सुन्दरता की अनुभूति के साथ सभी राम भक्त रामलीला का आनन्द ले सकें, साथ ही साथ फूडकोर्ट में पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी के अलावा, मथुरा, आगरा, बनारस, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, गुजरात आदि के चट-पट्टे जायके, आकर्षक झूले भी उपलब्ध रहेंगे।

फिल्म अभिनेता किंशुक वैध ने कहा कि मैंने अनेको फिल्मों एवं टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिला मैदान की विश्व विख्यात लव कुश रामलीला में प्रभु श्रीराम का किरदार करना मेरा सौभाग्य है। रिनी आर्या के अनुसार लालकिला मैदान दिल्ली में माता सीता का रोल करूंगी यह मेरे लिए बहुत चलेंजिंग है। इसके लिए मैं अभी से रिहर्सल कर रही हूँ। मल्हार पांड्या ने बताया कि मैं हनुमान जी का अट्ट भक्त हूँ यह मेरे लिए गौरव की बात है कि लव कुश रामलीला में बलशाली पवन पुत्र हनुमान का किरदार लाखों दर्शकों के सामने लाईव करूंगा ।

कमेटी के चैयरमेन पवन गुप्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषन जैन ने भी प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, दिव्यांगों को सामान वितरण किया जायेगा। महिलाओं के सम्मान की कड़ी में साड़ी वितरण, स्कूली बच्चों को स्कूल बेग, स्टेशनरी आदि वितरित की जायेगी तथा इस अवसर पर विशाल भण्डारा भी लगाया जायेगा। लीला स्थल लालकिला मैदान पर रामलीला से पूर्व विश्व विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति का कार्यकम सम्पन्न होगा।

नवोदय विद्यालय समिति
शिक्षा मंत्रालय के अर्तगत स्वायत्तशासी संस्था विभाग
स्कूल शिक्षा और साक्षरता, भारत सरकार

नवोदय विद्यालय समिति को विज्ञान ज्योति परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित परियोजना कार्मिको की आवश्यकता है। अवधिः एक वर्ष (अथगं, परियोजना अवधि के साथ सह- समाप्ति)

क. सीनीयर प्रोजेक्ट असोसिएट (रु.42,000/-+एचआरए) : 1 पद
ख. प्रोजेक्ट असोसिएट-1 (रु. 31,000/- + एचआरए) : 1 पद
ग. प्रोजेक्ट असोसिएट (रु.20,000/- + एचआरए) : 1 पद

इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर 2025 तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन ईमेल vigyanjyotinvs@gmail.com पर भेज सकते हैं। आवश्यक और वांछनीय योग्यता, आवेदन प्रारूप और अन्य शर्तों के विवरण के लिए, न.वि.स. वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर जाएं।

परियोजना समन्वयक

दिल्ली विकास प्राधिकरण
विज्ञापन स. : 08/परामर्शदाता/2025/भर्ती प्रकोष्ठ/कार्मिक/डीडीए

सूचना
डीडीए में अल्पावधि संविदा आधार पर परामर्शदाता (जीआईएस) की नियुक्ति

दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि प्रबंधन विभाग, डीडीए के लिए पूर्णतः अल्पावधि संविदा आधार पर 05 परामर्शदाता (जीआईएस) को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव रखता है।

इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन माध्यम से ईमेल : consultant.rc@dda.org.in पर दिनांक 23.09.2025 को या उससे पूर्व जमा करें।

पूर्ण अधिसूचना, बायो–डाटा प्रारूप आदि हेतु कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in → जॉब्स → सलेक्ट जॉब कैटेगरी → जॉब्स 2025-26 देखें।

हस्ता/-
आयुक्त (कार्मिक)

हमें फॉलो करें ddaofficial official_dda official_dda_
"कृपया वि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा 1800110332 डायल करें"

MORARJI DESAI NATIONAL INSTITUTE OF YOGA
Ministry of Ayush, Government of India
68, Ashok Road, New Delhi-110001
Ph. 23730417-18, 23351099. Telefax: 011-23711657
Email: dir-mdniy@nic.in, Website: www.yogamdniy.nic.in

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview for engagement on the following positions on purely temporary contract basis at Morarji Desai National Institute of Yoga (MDNIY), 68, Ashok Road, New Delhi-110001.

Sl. No.	Name of the Post	Number of the Post	Maximum Remuneration	Date of Walk-in-Interview
1.	Senior Consultant (Yoga Therapy)	01	Rs. 75,000/- P.M.	16.09.2025
2.	Domain Expert (Naturopathy)	01	Rs. 75,000/- P.M.	
3.	Senior Consultant (Medical)	01	Rs. 75,000/- P.M.	
4.	Project Coordinator WHO-CC Traditional Medicine Project) (one) For MDNIY	01	Rs. 75,000/- P.M.	17.09.2025
5.	Junior Hindi Translator (JHT)	01	Rs. 50,000/- P.M.	
6.	Research Associate (Yoga) (For Yoga Therapy Centres of MDNIY)	04	Rs. 47,000/- + HRA (as per rule)	
7.	Yoga Therapist for Yoga **Therapy & Training Centres at Government Ayurvedic Hospital, Jammu, Government Unani Hospital, Shalteng, Srinagar & National Institute of Sowa Rigpa, Leh, Ladakh**	06	Rs. 38,000/- P.M.	18.09.2025
8.	Yoga Instructor for **Yoga Therapy & Training Centres at Government Ayurvedic Hospital, Jammu & Government Unani Hospital, Shalteng, Srinagar & National Institute of Sowa Rigpa, Leh, Ladakh**	04	Rs. 32,000/- P.M.	
9.	Junior Research Fellow (JRF) (For Yoga Therapy Centres of MDNIY)	01	Rs. 31,000/- + HRA (as per rule)	

Note: The number of vacancies may increase or decrease as per requirement.
* Rs. 50,000/- P.M. plus TA OR Last pay drawn minus basic pension as per Ministry of Ayush letter No. A-41021/4/2020-E-II dated 01.04.2023 plus TA.
The detailed advertisement with the essential qualifications, experience and other terms & conditions of engagement to the above mentioned posts, and other associated information, etc, may be obtained from the Institute's website www.yogamdniy.nic.in
Interested candidates possessing the requisite qualifications, experience, etc. may attend the walk-in-interview along with CV, two passport size photographs and related documents along with copies of testimonials duly self-attested on the date of interview as mentioned above.
MDNIY reserves the right to cancel the above advertisement or any of the post without assigning any reasons.
CBC 17213/12/0003/2526
ADMINISTRATIVE OFFICER

Society for Electronic Transactions and Security (SETS)
(Under O/o the Principal Scientific Adviser to the Government of India),
MGR Knowledge City, CIT Campus, Taramani, Chennai-600113. Ph: 044-66632504, Fax: 044-66632501.

Advt No. SETS/Chn/Rec/2025-26/42 Date: 1st September 2025

Society for Electronic Transactions and Security (SETS) **invites online applications** from enthusiastic/ energetic researchers in the **area of Cybersecurity** focusing on the key verticals, namely, Cryptology and Computing, Hardware Security, Quantum Security and Network Security to fill up the following Positions on **Direct Recruitment Mode:**

Name of Post	Pay Level	No. of Posts	Mode of Recruitment
SCIENTIST-C	Pay Level-11 (Rs.67,700-2,08,700)	3 Posts	Direct

For details, please visit **www.setsindia.in/careers**
Last Date for receiving applications is **10.11.2025 @ 6 p.m.**
CAAO, SETS

तरक़्क़ी के शहर, अकेलेपन के घर

(सुविधाओं की उपलब्धता ने जीवन आसान बनाया, पर सामुदायिक विश्वास, आत्मीयता और सामाजिक बंधन टूटने लगे हैं।)

सबसे बड़ी चुनौती है सामुदायिक बंधनों का क्षरण। गाँवों में जहाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच गहरे संबंध होते हैं, वहीं शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अनजानेपन और दूरी का अनुभव करते हैं। गेटेड सोसाइटी और उच्च-आय वर्गीय कॉलोनियों ने सामाजिक जीवन को खंडित कर दिया है। लोग अपने छोटे-से घेरे में सिमट जाते हैं और ₹अन्य₹ के प्रति अविश्वास पनपने लगता है। यह प्रवृत्ति समाज में सामूहिक विश्वास और सहयोग की भावना को कमजोर करती है। शहरी जीवन का दूसरा बड़ा संकट है अकेलापन। भीड़भाड़ और व्यस्तता के बावजूद लोग व्यक्तिगत रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं।

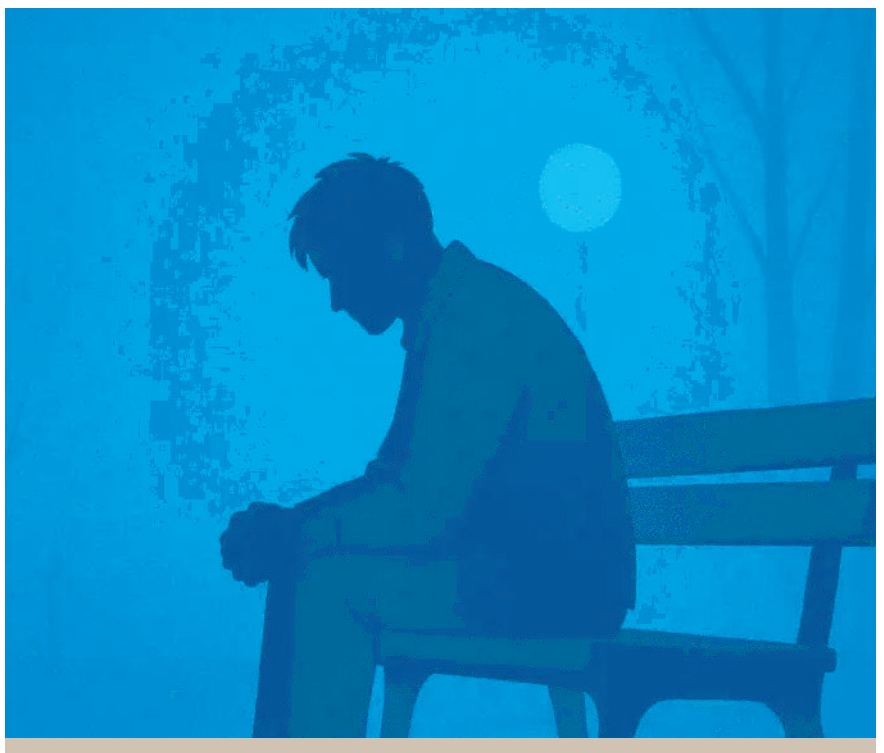

तकनीक ने भी इस अकेलेपन को बढ़ाया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता ने वास्तविक मानवीय बातचीत को सीमित कर दिया है। मेट्रो या बस में सफर करते हुए अक्सर लोग एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं। यह प्रवृत्ति समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल की उस धारणा को सही साबित करती है जिसमें उन्होंने आधुनिक शहरों को "भीड़ में अकेलेपन" का प्रतीक कहा था।

- डॉ प्रियंका सौरभ

महानगरों में लाखों लोग रहते हैं, परंतु अधिकांश अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने स्वीकार किया कि वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह आँकड़ा दिखाता है कि आधुनिक शहरी जीवन ने भले ही हमें भौतिक सुविधाएँ दी हों, परंतु भावनात्मक और सामाजिक रूप से हमें कमजोर किया है। तकनीक ने भी इस अकेलेपन को बढ़ाया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता ने वास्तविक मानवीय बातचीत को सीमित कर दिया है। मेट्रो या बस में सफर करते हुए अक्सर लोग एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं।

शहरीकरण ने भारत के सामाजिक जीवन और मानवीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। यह केवल आर्थिक प्रगति का साधन नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन भी है जिसने हमारे पारंपरिक रिश्तों, विश्वास और आपसी सहयोग की प्रकृति को बदल दिया है। शहरी जीवन की रफ्तार, अवसरों की विविधता और सेवाओं तक आसान पहुँच ने निश्चित ही नागरिकों को नए विकल्प दिए हैं, परंतु इसके साथ ही यह प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं और सामुदायिक रिश्तों को भी चुनौती देती रही है।

शहरों के विस्तार ने लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे अवसरों के करीब लाया। पहले जहाँ ग्रामीण भारत में इन सुविधाओं तक पहुँच कठिन थी, वहीं शहरी क्षेत्रों ने इन्हें आसान बनाया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में विश्वस्तरीय अस्पताल, विश्वविद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं। यह स्थान केवल सेवाएँ ही उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के मंच भी बनते हैं। इसी वजह से शहरी जीवन को आधुनिक भारत का इंजन कहा जाता है। यहाँ के निवासी विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे विविधता का अनुभव होता है और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है।

साथ ही, शहरी जीवन में सांस्कृतिक समृद्धि और नागरिक चेतना भी प्रबल होती है। कला दीर्घाएँ, पुस्तकालय, रंगमंच, साहित्यिक सभाएँ और जनआंदोलन जैसी गतिविधियाँ शहरों की पहचान रही हैं। चाहे वह कोलकाता की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स हो या दिल्ली का इंडिया हैबिटेट सेंटर—ये स्थान सामूहिक संवाद और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु जैसे शहरों में आईटी उद्योग और स्टार्टअप संस्कृति ने पेशेवर सहयोग और नेटवर्किंग की नई संभावनाएँ खोली हैं। नागरिक स्वयं भी संगठित होकर अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। गुरुग्राम की आवासीय कल्याण समितियों द्वारा कचरा प्रबंधन और जलभराव के खिलाफ अभियान इसका उदाहरण हैं।

लेकिन इन सब सकारात्मक पहलुओं के बीच शहरीकरण का एक दूसरा चेहरा भी है, जो कहीं अधिक गहन सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ी चुनौती है सामुदायिक बंधनों का क्षरण। गाँवों में जहाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच गहरे संबंध होते हैं, वहीं शहरों में रहने वाले लोग अक्सर अनजानेपन और दूरी का अनुभव करते हैं। गेटेड सोसाइटी और उच्च-आय वर्गीय कॉलोनियों ने सामाजिक जीवन को खंडित कर दिया है। लोग अपने छोटे-से घेरे में सिमट जाते हैं और ₹अन्य₹ के प्रति अविश्वास पनपने लगता है। यह प्रवृत्ति समाज में सामूहिक विश्वास और सहयोग की भावना को कमजोर करती है।

शहरी जीवन का दूसरा बड़ा संकट है अकेलापन। भीड़भाड़ और व्यस्तता के बावजूद लोग व्यक्तिगत रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं। महानगरों में लाखों लोग रहते हैं, परंतु अधिकांश अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत शहरी भारतीयों ने स्वीकार किया कि वे खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह आँकड़ा दिखाता है कि आधुनिक शहरी जीवन ने भले ही हमें भौतिक सुविधाएँ दी हों, परंतु भावनात्मक और सामाजिक रूप से हमें कमजोर किया है।

तकनीक ने भी इस अकेलेपन को बढ़ाया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर निर्भरता ने वास्तविक मानवीय बातचीत को सीमित कर दिया है। मेट्रो या बस में सफर करते हुए अक्सर लोग एक-दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन में डूबे रहते हैं। यह प्रवृत्ति समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल की उस धारणा को सही साबित करती है जिसमें उन्होंने आधुनिक शहरों को ₹भीड़ में अकेलेपन₹ का प्रतीक कहा था।

साथ ही, शहरी जीवन की भीड़-भाड़ और संसाधनों की कमी ने तनाव और संघर्ष को भी जन्म दिया है। पानी, बिजली, यातायात और पार्किंग जैसे मुद्दों पर झगड़े आम हो गए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में पार्किंग विवाद कई बार हिंसा तक पहुँच जाते हैं। वाहन प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाएँ भी नागरिक जीवन की असुरक्षा को बढ़ाती हैं। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थान कम होते जा रहे हैं, जिससे साझा सार्वजनिक जीवन घटता जा रहा है। यह कमी सामाजिक पूँजी पर सीधा आघात करती है, क्योंकि खुले और सुरक्षित सार्वजनिक स्थल ही लोगों के बीच संवाद और सहयोग को जन्म देते हैं।

इस प्रकार, शहरीकरण ने भारत के सामाजिक पूँजी पर दोतरफा असर डाला है। एक ओर इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, विविधता और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर दिए, तो दूसरी ओर इसने रिश्तों को सतही, अस्थिर और अविश्वासी बना दिया। आर्थिक विकास की गति में हमने भावनात्मक और सामुदायिक जीवन को पीछे छोड़ दिया।

आवश्यक है कि शहरी नियोजन केवल भौतिक ढाँचे तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें मानवीय संबंधों की गरिमा और सामुदायिक जीवन की बहाली को भी स्थान मिले। हमें ऐसे सार्वजनिक स्थल चाहिए जहाँ लोग सहजता से मिल सकें और संवाद कर सकें। आवासीय कल्याण समितियों को केवल प्रशासनिक इकाई न मानकर सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक उत्सवों का मंच बनाया जाए। शहरों में त्योहारों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग एक-दूसरे के करीब आ सकें। साथ ही, सस्ते और समावेशी आवास की नीतियाँ तैयार हों, जिससे वर्ग आधारित विभाजन कम हो सके।

भारत का भविष्य निस्संदेह शहरी होगा, परंतु यह भविष्य तभी स्थायी और समृद्ध हो सकता है जब शहरीकरण केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक पूँजी का भी संवाहक बने। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास की दौड़ में रिश्तों का ताना-बाना न टूटे। शहर तभी सच्चे अर्थों में प्रगतिशील बनेंगे जब वे न केवल समृद्धि और अवसर देंगे, बल्कि विश्वास, सहयोग और सामूहिक कल्याण की भावना को भी जीवित रखेंगे।

भागवत पीठ में विराट सन्त-विद्वत सम्मेलन के साथ हुआ सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत जयंती एवं श्रीराधाष्टमी महोत्सव का समापन

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रुक्मिणी विहार रोड़ (निकट केशव धाम) स्थित भागवत पीठ आश्रम में सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान (रजि.) के द्वारा ब्रज विभूति परिव्राजकाचार्य स्वामी ब्रजरमणाचार्य महाराज व विद्वत शिरोमणि भागवत भूषण आचार्य पीठाधिपति स्वामी किशोरीरमणाचार्य महाराज की पावन स्मृति में चल रहा सप्त दिवसीय 49वां श्रीमद्भागवत जयंती एवं श्रीराधाष्टमी महोत्सव विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ।इस अवसर पर आयोजित विराट संत-विद्वत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए आचार्य कुटी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामप्रपन्नाचार्य महाराज एवं श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि श्रीराधा तत्व प्रेम का वह परम दिव्य भाव है, जो श्रीकृष्ण के साथ मिलकर आनंद और भक्ति का अद्भुत अनुभव कराता है।कुछ परंपराओं में कृष्ण और राधा को एक ही पूर्णतम परब्रह्म के दो रूप माना गया है, जो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अलग-अलग लीलाएँ करते हैं।

श्रीनाभापीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज एवं संत प्रवर स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि वर्तमान में सनातन धर्म पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, उसके लिए हम सभी को एकत्र होकर आगे आना होगा।यदि हम जातियों ने बंटे रहे,तो एक दिन भारत से ही विलोप हो जायेंगे।भारत देश सनातनियों का देश है और हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी होगी।

आचार्य/भागवत पीठाधीश्वर भागवत प्रभाकर मारुति नंदनाचार्य ₹वागीश₹ महाराज एवं युवराज श्रीधराचार्य महाराज ने कहा कि आचार्य/भागवत पीठ धर्म व अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है।यहां पर सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान (रजि.) के द्वारा वर्ष में तीन आयोजन (फाग महोत्सव, झूलन महोत्सव एवं श्रीमद्भागवत जयंती/श्रीराधाष्टमी महोत्सव) अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ प्रख्यात संतों, विद्वानों एवं धर्माचार्यों की उपस्थिति में मनाए जाते हैं

गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य महाराज एवं धर्मरत्न स्वामी बलरामाचार्य महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण कोई साधारण ग्रन्थ नही है, बल्कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण का वांग्मय स्वरूप है।इसके प्रत्येक श्लोक में श्रीराधा-कृष्ण विद्यमान हैं।इसीलिए इसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति के तीनों तापों का नाश हो जाता है।साथ ही उसे प्रभु की दुर्लभ भक्ति प्राप्त होती है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान (रजि.) के द्वारा धर्म के क्षेत्र में श्रीराम कथा मर्मज्ञ संत विजय कौशल महाराज, शिक्षा के क्षेत्र में कान्हा माखन ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन अनिल अग्रवाल एवं संगीत कला के क्षेत्र में भक्तिमती उप्रेती सिस्टर्स (उत्तराखंड) आदि को ₹प्रज्ञा रत्न₹ की उपाधि से अलंकृत किया गया। तत्पश्चात्प्रवचन प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं दक्षिणा आदि प्रदान कर पुरुस्कृत किया गया।

संत-विद्वत सम्मेलन में आचार्य ललित किशोर व्यास महाराज, श्रीहरदेव पीठाधीश्वर स्वामी नारायणाचार्य महाराज, भजन गायक बनवारी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानन्द महाराज, केडी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन और प्रमुख समाजसेवी रामकिशोर अग्रवाल, मथुरा-वृंदावन नगर निगम के उप-सभापति मुकेश सारस्वत, संत रामदास महाराज (अयोध्या), श्रीदाम किंकर महाराज, आचार्य नेत्रपाल शास्त्री, आचार्य वल्लभ महाराज, राजेश पाण्डेय, प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, पूर्व प्राचार्य डॉ. राम सुदर्शन मिश्रा, डॉ. राधाकांत। शर्मा, श्याम सुन्दर ब्रजवासी, आचार्य घनश्याम दुबे, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, पण्डित भरत शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।संचालन आचार्य नरोत्तम शास्त्री ने किया एवं महोत्सव के समन्वयक डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया।महोत्सव का समापन संत, ब्रजवासी, वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ।

देखिए योगी जी ! शिकायतों के बाद भी पुलिस नहीं कर रही शुक्लागंज के दबंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई : दर्जनों भयभीत

सुनील बाजपेई

कानपुर। योगी सरकार के दावों को ठेंगा दिखाते हुए कई जनपदों में लगातार सक्रिय ऊंची पहुंच वाले दबंग माफिया लोगों को अपना शिकार बनाने में लगातार सफल हैं। इनकी ऊंची पहुंच और प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस तरह के प्रभावशाली माफियाओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र तो देना दूर लोग जुबान खोलने से भी डरते हैं। और जो ऐसे प्रभावशाली दबंगों के खिलाफ साहस करता भी है तो वह उसके खिलाफ सफल नहीं होता, क्योंकि दबंग माफिया किसी न किसी हथकंडे से अपने खिलाफ शिकायत को रफा दफा करवा देता है। मतलब पुलिस के प्रार्थना पत्र पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि वह दबंग माफिया दूसरों के मकानों ,दुकानों ,भूखंडों पर जबरन कब्जों के साथ ही रंगदारी वसूलने में लगातार सफल होता चला जाता है। कुछ इसी तरह के गंभीर आरोपों को लेकर अहमदनगर शुक्लागंज उन्नाव के वीरेंद्र चतुर्वेदी की दबंगई और पुलिस प्रशासन पर उसका अपने पक्ष में जबरदस्त प्रभाव भी चर्चा का विषय बना हुआ हैं।

स्थानीय लोगों और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्लागंज इलाके के इस चर्चित दबंग वीरेंद्र चतुर्वेदी से भयभीत पीड़ित लोगों की संख्या एक आध बल्कि दर्जनों में बताई जाती हैं, जिनमें से एक नाम महताब पुत्र मोहम्मद मुस्तफा निवासी 377 गंगानगर, शुक्लागंज कटरी पीपरखेड़ा उन्नाव का भी है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन पर बहुत मजबूत पकड़ वाला दबंग कथित माफिया वीरेंद्र चतुर्वेदी ₹2 लाख की रंगदारी देने में असमर्थ होने की वजह से मेहताब को उसकी ही जमीन पर मकान का निर्माण नहीं करने दे रहा है। जबकि वह इसके पहले भी 2 लाख रुपए मेहताब से रंगदारी के रूप में वसूल भी चुका है। पीड़ित मेहताब इस बारे में पुलिस और प्रशासन के साथ ही शासन को भी प्रार्थना पत्र दे चुका है लेकिन आज तक दबंग वीरेंद्र चतुर्वेदी ने उसका मकान नहीं बनने दिया।

इस बारे में पीड़ित मेहता द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक उसने ग्राम सभा कटरी पीपरखेड़ा में पुरानी भूखण्ड सं० 52 और अब नयी भूखण्ड सं० 91ख रकबा 78.99 वर्ग मीटर पूर्व प्लाट मालिक हरीराम पुत्र दर्शन से दिनांक 22 दिसंबर 2020 को क्रय किया था ,जिसमें वर्तमान में 6 फिट की बाउण्ड्री वगेट भी लगा हुआ है। अब वह अपने इसी भूखंड में अपना मकान बनाना चाहता है लेकिन क्षेत्रके दबंग व अपराधिक प्रवृत्ति के भूमाफिया वीरेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र सत्यचरन चतुर्वेदी निवासी अहमदनगर शुक्लागंज उन्नाव उसे अपना मकान बनाने नहीं दे रहा है। वह इसके लिए दो लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहा है, जबकि ₹2 लाख की रंगदारी पहले भी वसूल चुका है। और नहीं देने पर प्लाट पर जबरन कब्जा कर लेने तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी अपने साथियों क्रमशः दिलशाद उर्फ अंकल, आकाश मिश्रा, निवासी अहमदनगर शुक्लागंज आदि के साथ मिलकर दे रहा है। दबंग वीरेंद्र चतुर्वेदी के खिलाफ कई गम्भीर आपराधिक मुकदमें भी दर्ज हैं।

फिलहाल पीड़ित महताब ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सहायता की गुहार लगाई है ,लेकिन क्या उसे न्याय वास्तव में मिल पाएगा या फिर दबंग माफिया को 2 लाख की रंगदारी देने के बाद ही वह अपना मकान बना पाएगा। इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।

बाजार जगत व व्यावसायिक वर्ग अलर्ट मोड पर रहें ?वित्तमंत्री का सख़्त रुख-कर कटौती का लाभ आम जनता तक पहुंचानें व्यक्तिगत रूप निगरानी का ऐलान !

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

भारत की आर्थिक संरचना में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों को ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। 2017 में जब इसे लागू किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था-"एक राष्ट्र,एक टैक्स" की अवधारणा के तहत पूरे देश को एकीकृत करना और कर ढांचे की जटिलताओं को कम करना। अब 2025 में, सरकार ने जीएसटी सुधारों की नई श्रृंखला लागू करते हुए कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की है।यह कदम सीधे तौर पर महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को राहत देने वाला माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कर कटौती का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचेगा ? क्या व्यवसायी वर्ग इस राहत को उपभोक्ताओं तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाएंगे ? और क्या अंतरराष्ट्रीय दबावों जैसे ट्रंप प्रशासन के 50 पर्सेंट टैरिफ फैसलों का कोई प्रभाव इन सुधारों पर पड़ा है ?मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं जीएसटी दरों में कटौती से तुरंत उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कर घटने पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर स्थिति इतनी सरल नहीं होती।बाजार में अक्सर देखा गया है कि व्यापारी या निर्माता अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए कीमतों में उतनी कटौती नहीं करते, जितनी कर दरों में कमी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर पहले 18 पर्सेंट जीएसटी था और अब उसे 12 पर्सेंट या जीरो कर स्लैब में लाया गया है, तो कीमत में 6 पर्सेंट या 18 पर्सेंट की कटौती होनी चाहिए। लेकिन कई बार यह अंतर उपभोक्ताओं तक मात्र 2-3 पर्सेंट ही पहुंचता है। यही कारण है कि आम जनता के मन में भ्रम बना हुआ है कि क्या यह सुधार वास्तव में उनके लिए हैं या केवल उद्योग जगत के लिए।इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे जीएसटी सुधार 2025-जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचना सबसे बड़ी चुनौती

साथियों बात अगर हम केंद्रीय वित्तमंत्री के 6 सितंबर 2024 को सख्त रुख और निगरानी के ऐलान की करें तो उन्होंने इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से व्यवसायों द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। यह बयान जनता में विश्वास जगाने वाला है, क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीयमंत्री ने इतनी सख्ती से कहा है कि वह लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नजर रखेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि 22 सितंबर के बाद बहुत बड़ा सतर्कता अभियान चलाया जाएगा,ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर कटौती का असर कीमतों पर दिखे।सरकार ने इस निगरानी अभियान को केवल वित्त मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा है। सांसदों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में बाजार दरों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इनको सख़्ती से अगले एक से डेढ़ महीने तक सतत निरीक्षण का काम सौंपा गया है। सीबीआईसी यह देखेगा कि कर कटौती का असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है या नहीं। इस तरह एक बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र बनाया गया है ताकि कहीं भी लापरवाही या हेराफेरी की गुंजाइश न रहे।

साथियों बात अगर हम सरकार के कड़क संदेश की करें तो "लाभ न पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा" स्पष्ट वक्तव्य कि लाभ पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बाजार जगत को सीधा संदेश देता है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि व्यवसायिक वर्ग सावधानी बरतेगा और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने में सहयोग करेगा।यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं,बल्कि सरकार की उस गंभीरता का प्रतीक है जो वह जनता को राहत देने के लिए दिखा रही है।

साथियों बात अगर हम उपभोक्ताओं को भी जागृत होने की करें तो,सिर्फ सरकार की निगरानी ही पर्याप्त नहीं है। उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना होगा कि वे बाजार में घटे हुए कर दरों का लाभ पा रहे हैं या नहीं। यदि व्यापारी कीमत कम नहीं करता तो उपभोक्ता को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। भारत में उपभोक्ता अदालतें और हेल्पलाइन मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग उनका उपयोग नहीं करते। जीएसटी सुधारों का असली फायदा तभी मिलेगा जब जनता भी सक्रिय होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी।डिजिटल बिलिंग और ई-इनवॉयसिंग व्यवस्था जीएसटी सुधारों को और प्रभावी बनाती है।अब हर लेनदेन की डिजिटल रिकॉर्डिंग होने लगी है, जिससे कर चोरी की संभावना कम होती है। इससे यह भी आसान हो जाएगा कि कर दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता कीमतों में परिलक्षित हो रहा है या नहीं। सरकार को चाहिए कि वह डिजिटल ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर कीमतों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखे।

साथियों बात अगर हम जीएसटी 1.0 से जीएसटी 3.0 तक का सफर की करें तो,वित्त मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि जीएसटी 1.0 (2017) का उद्देश्य राष्ट्र को एकीकृत करना था। इसके बाद जीएसटी 2.0 (2025) का फोकस "सरलता" पर है, ताकि कर ढांचे को आम व्यवसायियों और जनता के लिए आसान बनाया जा सके। उन्होंने संकेत दिया कि जीएसटी 3.0 भविष्य में और भी व्यापक सुधार लेकर आएगा। संभव है कि इसमें पेट्रोलियम उत्पादों और कुछ अन्य जटिल कर ढांचों को भी शामिल किया जाए। इस तरह भारत की कर व्यवस्था धीरे-धीरे अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता- हितैषी बन सकती है।भारत जैसे विशाल देश में महंगाई केवल कर ढांचे की वजह से नहीं, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक तेल कीमतों और मौसमी उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करती है। फिर भी कर कटौती से कुछ हद तक राहत मिलना तय है। यदि व्यवसायी वर्ग ईमानदारी से लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए तो दाल, चीनी, पैक्ड फूड, कपड़े और घरेलू उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी देखी जा सकती है। यह सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को मजबूत करेगा।भविष्य की राह,जीएसटी 3.0 से उम्मीदें- विशेषज्ञ मानते हैं कि जीएसटी 3.0 भारत की कर व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसमें न केवल पेट्रोल-डीजल को शामिल किया जा सकता है, बल्कि वर्तमान कर स्लैब को और सरल किया जा सकता है। साथ ही, छोटे व्यवसायियों के लिए अनुपालन की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत का जीएसटी मॉडल विश्व स्तर पर एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष की करें तो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य-ट्रंप के टैरिफ से तुलना,कईविशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या ये सुधार ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50 पर्सेंट टैरिफ के मद्देनजर पेश किए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव को संतुलित करने के लिए घरेलू कर सुधार दिखा रही है। लेकिन वित्त मंत्री ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पिछले डेढ़ साल से इन सुधारों पर काम कर रही है और यह प्रक्रिया घरेलू जरूरतों से प्रेरित है, न कि अंतरराष्ट्रीय दबाव से। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की कर नीति को घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं और महंगाई नियंत्रण के नजरिए से आगे बढ़ाया जा रहा है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जीएसटी सुधार 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम है। यह केवल कर दरों में कटौती का मामला नहीं,बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास बनाने का प्रयास भी है। यदि व्यापारी वर्ग ईमानदारी से कर कटौती का लाभउपभोक्ताओं तक पहुंचाए और सरकार निगरानी में सख्ती दिखाए तो यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी यहदिखाएगा कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों और जनताकी भलाई को प्राथमिकता देता है, चाहे वैश्विक दबाव कुछ भी क्यों न हों।आने वाले वर्षों में जीएसटी 3.0 से और भी बड़ी उम्मीदें हैं,और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का भविष्य काफी हद तक इस कर ढांचे की सफलता पर निर्भर करेगा।

हुंडई ने की बड़ी घोषणा, जीएसटी में कटौती के बाद अपनी कारों की कीमतों में की भारी कमी, पढ़ें लिस्ट

हुंडई की कीमतें भारत में हुंडई मोटर की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा होने के बाद अपनी कारों की कीमत कम कर दी है। किस कार की कीमत में कितनी कमी की गई है। अब कब से कम कीमत पर इनको खरीदा जा सकता है।

नई दिल्ली। भारत में जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अब सभी वाहन निर्माता अपनी कारों की कीमत में कमी कर रहे हैं। जिसके बाद हुंडई मोटर की ओर से अभी यह घोषणा कर दी गई है। निर्माता की ओर से किस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी की गई है। इसे कब से लागू किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई की कारों की कीमत हुई कम

हुंडई मोटर की ओर से जानकारी दी गई है कि वह भी अपनी कारों की कीमत में कमी कर रही है। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद ऐसा किया जा रहा है।

किस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी

निर्माता की ओर से बताया गया है कि वह अपनी सभी कारों की कीमत को कम करेगी। Hyundai Grand Nios i10 की कीमत में 73808 रुपये, ऑरा की कीमत में 78465 रुपये, एक्सटर की कीमत में 89209 रुपये, आई-20 की कीमत में 98 हजार रुपये, आई-20 एन लाइन की कीमत में 1.08 लाख रुपये, वेन्यू की कीमत में 1.23 लाख रुपये, वेन्यू एन लाइन की कीमत में 1.19 लाख रुपये, वर्ना की कीमत में 60 हजार रुपये, क्रेटा की कीमत में 72 हजार रुपये, क्रेटा एन लाइन की कीमत में 71 हजार रुपये, अल्काजार की कीमत में 75 हजार रुपये और ट्यूसॉन की कीमत में 2.40 लाख रुपये तक कम किए गए हैं।

कब से कीमत होंगी कम

हुंडई की ओर से बताया गया है कि वह इन कीमतों को 22 सितंबर से लागू करेगी। जिसके बाद देशभर में कम कीमत पर हुंडई की कारों को खरीदा जा सकता है।

अधिकारियों ने कही यह बात

हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उन सो किम ने कहा कि हम यात्री वाहनों पर जीएसटी कम करने के भारत सरकार के प्रगतिशील और दूरदर्शी कदम की सराहना करते हैं। यह सुधार न केवल ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि व्यक्तिगत परिवहन को और अधिक किफायती और सुलभ बनाकर लाखों ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मज़बूत कदम भी है। जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हुंडई अपनी कारों और एसयूवी के माध्यम से मूल्य, नवीनता और ड्राइविंग का आनंद प्रदान करते हुए देश की विकास महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार ने की थी घोषणा

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि वाहनों पर लगने वाली जीएसटी की स्लैब को बदला जाएगा। जिसके बाद अधिकतर वाहनों की कीमत में कमी की गई है।

टाटा ने किया बड़ा ऐलान, जीएसटी में कटौती के बाद कमर्शियल वाहनों की कीमत में 4.65 लाख तक की आई

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से निजी वाहनों के साथ ही कमर्शियल सेगमेंट में भी वाहनों की बिक्री की जाती है। जीएसटी में कटौती के बाद अब निर्माता ने अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में भी कटौती कर दी है। किस सेगमेंट के वाहनों की कीमत में कितनी कमी की गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख कमर्शियल वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में बड़ी कटौती करने की घोषणा की है। निर्माता की ओर से जीएसटी की दरों में कटौती के बाद किस सेगमेंट के वाहनों की कीमत में कितनी कमी की है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata ने की कटौती

टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल सेगमेंट के वाहनों की कीमत में कटौती करने की घोषणा कर दी है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कमर्शियल सेगमेंट के वाहनों की कीमत में 4.65 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की गई है।

किस सेगमेंट में कितनी कटौती

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक SCV और पिकअप की कीमत में 30 हजार रुपये से 1.10 लाख रुपये तक कम किए गए हैं। SCV पैसेंजर वाहनों की कीमत में 52 हजार रुपये से 66 हजार रुपये तक कम किए गए हैं। बस और वैन की कीमत में 1.20 लाख रुपये से 4.35 लाख रुपये तक कम किए गए हैं। ILMCV सेगमेंट के वाहनों की कीमत को एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक कम किया गया है और HCV सेगमेंट के वाहनों की कीमत को टाटा मोटर्स ने 2.80 लाख रुपये से 4.65 लाख रुपये तक कम किया गया है।

कब से लागू हो रही कीमत

निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह इन कीमतों को 22 सितंबर से लागू कर देगी। जिसके बाद देशभर में इन वाहनों को खरीदने के लिए कम कीमत देनी होगी। जिससे आने वाले त्यौहारों में भी लोगों को लाखों रुपये का फायदा मिल पाएगा।

सरकार ने की थी घोषणा

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि वाहनों पर लगने वाली जीएसटी की स्लैब को बदला जाएगा। जिसके बाद अधिकतर वाहनों की कीमत में कमी की गई है।

वोक्सवैगन की गाड़ियों पर जबरदस्त डिस्काउंट, 3 लाख रुपये तक की दी जा रही छूट

फेस्टिव सीजन में Volkswagen इंडिया ने सितंबर 2025 में Tiguan Taigun और Virtus जैसे चुनिंदा मॉडलों पर भारी छूट का एलान किया है। Tiguan पर 3 लाख रुपये तक की छूट है जबकि Taigun पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। Virtus के 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले टॉपलाइन वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Volkswagen इंडिया ने सितंबर 2025 में अपने चुनिंदा मॉडलों पर भारी छूट का एलान किया है। Tiguan, Taigun और Virtus पर मिलने वाले डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स के चलते ये गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Volkswagen की गाड़ियों पर सितंबर 2025 में कितना डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है?

Volkswagen Tiguan पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 3 लाख रुपये तक की छूट

अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई नई जेनरेशन Volkswagen Tiguan के R Line वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपये रखी गई थी। इस फ्लैगशिप SUV पर इस महीने ग्राहकों को 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इसे 204hp की पावर जनरेट करने वाले 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर करती है। यह पावर चारों पहियों तक पहुंचाता है, जिससे SUV का परफॉर्मेंस और भी दमदार हो जाता है।

Volkswagen Taigun पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 1.55 लाख रुपये तक की छूट

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पॉपुलर Volkswagen Taigun पर भी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। टॉपलाइन 1.0 TSI AT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। हाईलाइन वेरिएंट पर 1 लाख रुपये और GT Line वेरिएंट्स 1.1 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके बेस कम्फर्टलाइन वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अब सिर्फ 10.99 लाख रुपये रखी गई है, जो एक्स-शोरूम प्राइस से 80,000 रुपये कम है। वहीं, GT 1.5 TSI (MT और DSG दोनों) पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।

Volkswagen Virtus पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 1.5 लाख रुपये तक की छूट

Volkswagen Virtus के 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले टॉपलाइन वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, कम्फर्टलाइन वेरिएंट की कीमत इस महीने 11.56 लाख रुपये से घटाकर 10.54 लाख रुपये कर दी गई है। Virtus के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट्स पर एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस के साथ करीब 90,000 रुपये तक की बचत संभव है। खास बात यह है कि 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट्स की कीमत में अस्थायी तौर पर 35,000 से 40,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

डिस्क्लेमर: यह डिस्काउंट्स डीलरशिप, स्टॉक अवेलेबिलिटी और जगह के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको खरीदारों को सलाह दी जाती है कि आप अपने नजदीकी Volkswagen शोरूम पर जाकर सही ऑफर्स की जानकारी जरूर लें।

क्यों खराब होते हैं गाड़ी के टायर, वो कारण जिनकी वजह से आते हैं क्रैक और कैसे बचाएं अपनी जान

कार टायर टिप्स भारत में सड़कों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। जिसके कारण लोग अपनी कार से भी सफर करना पसंद करने लगे हैं। कई लोग कार के साथ लापरवाही करते हैं और इसका नुकसान कार के टायरों को होता है। किन कारणों से कार के टायरों में क्रैक आ जाता है और टायर खराब हो जाते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। वैसे तो अपनी कार का ध्यान रखकर बिना परेशानी उसे लंबे समय तक चलाया जा सकात है। लेकिन कुछ लोग लापरवाही करते हैं और उनकी कार में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। लापरवाही का नुकसान कार के टायरों पर भी होता है और इनमें क्रैक जैसी परेशानी आ जाती है। इस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

लापरवाही से आते हैं क्रैक

कार में कितनी भी अच्छी क्वालिटी के टायर का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन अगर उनके साथ लंबे समय तक लापरवाही बरती जाती है तो फिर क रके टायर में कई तरह की परेशानियां आने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अक्सर मौसम बदलने और टायर के घिसने के कारण क्रैक आ जाते हैं।

कहां दिखाई देते हैं क्रैक

कार के टायर में सबसे ज्यादा क्रैक आने का खतरा साइड वॉल पर होता है। टायर के साइड वॉल पर अगर हल्की दरारें आ जाएं तो लापरवाही के कारण यह और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। टायर में क्रैक आने के बाद हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा टायर में क्रैक के कारण हवा जल्दी जल्दी निकलने लगती है। जिस कारण एवरेज पर भी बुरा असर होता है।

क्रैक आने का यह भी है कारण

अगर कार को काफी कम चलाया जाता है और अक्सर कार को एक ही जगह पर खड़ा रखा जाता है, तो भी गाड़ी के टायर में क्रैक आने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है जब टायर उपयोग में नहीं आते हैं और लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहने के कारण रबड़ सूखने लगती है।

इस परेशानी का क्या है समाधान

अगर आपकी कार के टायर में भी क्रैक आ जाएं तो फिर इनको पूरी तरह से ठीक नहीं करवाया जा सकता। कुछ लोग ऐसे टायर को ठीक करते हैं, लेकिन यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। ऐसे में इनको बदल कर नए टायर का उपयोग करना ही एकमात्र समाधान होता है।

स्कोडा की कारों को खरीदने का मिल रहा सबसे बेहतरीन मौका, जीएसटी में बदलाव के साथ मिल रहे कई फायदे

स्कोडा जीएसटी जीएसटी की दरों में बदलाव की घोषणा के बाद से वाहन निर्माताओं की ओर से भी कारों की कीमत में कमी की जा रही है। स्कोडा की ओर से भी हाल में ही बताया गया है कि वह भी अपनी कारों की कीमत को कम कर रही है। निर्माता किस कार की कीमत को कितना कम कर रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद वाहन निर्माताओं की ओर से अपनी कारों की कीमत में बदलाव किया जा रहा है। कई वाहन निर्माताओं के साथ ही Skoda की ओर से भी अपनी कारों की कीमत को नई जीएसटी की दरों के मुताबिक अपडेट कर दिया है। साथ ही निर्माता की ओर से और भी फायदों को अपनी कारों के साथ दिया जा रहा है। किस कार पर कितना फायदा मिल सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

स्कोडा ने की घोषणा

वाहन निर्माता स्कोडा की ओर से भी अपनी कारों की कीमत को कम करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इन फायदों को सीमित समय के लिए ऑफर किया जा रहा है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से लेकर मिड साइज सेडान कार और फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है।

किस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी

स्कोडा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक Skoda Kushaq की कीमत में 66 हजार रुपये तक कम कर दिए गए हैं। Skoda Slavia की कीमत में भी 63 हजार रुपये तक कम किए गए हैं। सबसे ज्यादा कमी निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली Skoda Kodiaq की कीमतों में की गई है। इस कार को अब खरीदना 3.3 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है।

मिल रहा अतिरिक्त फायदा

निर्माता की ओर से अपनी कारों पर जीएसटी में कमी के साथ ही अतिरिक्त फायदे भी दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक स्कोडा कुशाक पर 2.5 लाख रुपये, स्कोडा स्लाविया पर 1.2 लाख रुपये और स्कोडा कोडिएक पर भी 2.5 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा रहे हैं।

कब तक मिलेगा फायदा

स्कोडा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त फायदे को सीमित अवधि के लिए ऑफर किया गया है। अपनी कारों पर निर्माता की ओर से 21 सितंबर तक ही अतिरिक्त फायदे दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि निर्माता की ओर से इस तरह के ऑफर को अपनी सबसे सस्ती एसयूवी Skoda Kushaq पर नहीं दिया है।

मारुति XL6 अब पहले से और भी बेहतर, तीसरी रो में मिले ये 5 नए फीचर्स, क्या कीमत में हुआ बदलाव?

मारुतिXL6 देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से अपनी कारों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। इसी क्रम में अब Maruti XL6 को भी अपडेट किया गया है। इस एमपीवी में किस तरह के अपडेट किए गए हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki लगातार अपनी कारों को अपडेट कर रही है। इसी क्रम में Maruti Ertiga के बाद अब Maruti XL6 को भी अपडेट किया गया है। इस एमपीवी में किस तरह के फीचर्स को अपडेट किया गया है। अब इसकी क्या कीमत है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं

मारुति XL6 हुई अपडेट

मारुति की ओर से एमपीवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Maruti XL6 को अपडेट किया गया है। अपडेट के साथ ही इसमें कई नए फीचर्स को जोड़ा गया है। जिससे यह पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है।

क्या मिला अपडेट

जानकारी के मुताबिक मारुति की ओर से XL6 में अब नए डिजाइन का रियर स्पॉयलर दिया गया है। इसके साथ ही इसके किनारों पर काले रंग के इंसर्ट्स दिए गए हैं जो देखने में काफी स्पोर्टी लग रहे हैं। इसके अलावा इंटीरियर में भी दूसरी रो में दिए जाने वाले एसी वेंट्स को हटाया गया है। इसके अलावा तीसरी रो वालों के लिए भी एसी वेंट्स के साथ ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल को दिया गया है। एमपीवी में अपडेट के साथ दूसरी रो वालों के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसी तरह तीसरी रो में भी इस फीचर को दिया गया है।

इंजन में हुआ बदलाव?

मारुति की ओर से इस एमपीवी के इंजन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और सीएनजी इंजन दिया जा रहा है। इस इंजन से एमपीवी को 102 बीएचपी की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। इसके साथ पांच स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जाते हैं।

कितनी है कीमत

निर्माता की ओर से इस एमपीवी को 11.93 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपये है।

किनसे है मुकाबला

मारुति की ओर से XL6 को एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जा रहा है। छह सीटों वाली किसी भी एमपीवी को बाजार में ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन कीमत के मामले में इसे Maruti Ertiga, Kia Carens Clavis, Renault Triber से मुकाबला करना होता है।

विकास की रफ्तार और घटता रोजगार

विजय गर्ग

देश के आर्थिक विकास का पैमाना कुछ इस तरह होना चाहिए, जिसमें सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समानता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गरीबी और भुखमरी में गिरावट, सामाजिक असमानताओं में कमी, रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। एक समृद्ध लोकतंत्र में आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जहां व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हो और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास संभव हो। विकास का माडल ऐसा हो, जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ रही है। आने वाले तीन वर्षों में देश के पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।

एशियाई विकास बैंक के मुताबिक, भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसद और 2026 में 6.7 फीसद की दर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। भारतीय व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक असमानता, घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी है। । इस वक्त बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, जो देश के संपूर्ण विकास में अवरोधक है। उसी अर्थव्यवस्था को संतुलित माना जाता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्तूबर, 2022 से सितंबर, 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस कारण करीब 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां युवाओं की आबादी अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। हाल में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रपट के मुताबिक, देश में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6 फीसद, जबकि महिलाओं में 5.8 फीसद है। देश में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में इस वर्ष अप्रैल में बेरोजगारी 13.8 फीसद से बढ़कर मई में 15 फीसद हो गई। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल में 17.2 फीसद से बढ़कर मई में 17.9 फीसद हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अप्रैल के 12.3 फीसद की तुलना में मई में 13.7 फीसद थी।

हमारे यहां जनसंख्या और श्रमबल क्षमता अधिक होने के बावजूद आर्थिक असमानता भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही आर्थिक असमानता विकास की राह बड़ी बाधक है। आक्सफैम 2024 की एक रपट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, पिछले कई वर्षों से भारत समेत विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। यह आर्थिक तंत्र के लिए बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात है। आर्थिक असमानता के मामले में भारत के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल संपत्ति का चालीस फीसद हिस्सा देश के एक फीसद अमीर लोगों के पास है। वर्तमान में भारत के इक्कीस सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के सत्तर करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल तीन फीसद है। यहां अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 और 2023 में यह आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। इस तरह की आर्थिक असमानता से गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ती है और देश का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। अगर भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो इसे दूर करने संबंधी प्रयास निराशाजनक नजर आते हैं। बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इंडिया स्किल्स रपट-2025 के अनुसार, भारत में स्नातकों के बीच रोजगार योग्यता बढ़ कर 54.81 फीसद हो गई है।

वहीं, 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' की रपट से पता चलता है। कि भारत में हर वर्ष पचास लाख युवा उच्च शिक्षा की ओर रुख करते जिनकी उम्र करीब उन्नीस-बीस वर्ष होती है। ये युवा अपनी स्नातक की पढ़ाई लगभग 24 वर्ष की उम्र तक पूरी कर लेते हैं। जबकि भारत में पच्चीस वर्ष से कम उम्र के युवाओं में स्नातक स्तर पर बयालीस फीसद बेरोजगार हैं। परास्नातक की पढ़ाई करने के बाद या जिनकी उम्र पच्चीस से उनतीस वर्ष के बीच है, उनमें बेरोजगारी 22.8 फीसद है। इसी तरह तीस से पैंतीस वर्ष उम्र के पढ़े-लिखे युवाओं में बेरोजगारी 9.8 फीसद है। इससे ऊपर की उम्र के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर लगभग पांच फीसद है। देश में पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 में यह 5.44 फीसद और 2020 में आठ फीसद थी। वर्ष 2023 के अक्तूबर में बेरोजगारी दर 10.1 फीसद पर पहुंच गई थी।

भारत में श्रमबल की भागीदारी लगभग 46 फीसद है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर नजर डालें तो इसके कई कारण स्पष्ट नजर आते हैं। इनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक दिक्कतें, व्यावसायिक कौशल की कमी, खराब शैक्षिक उपलब्धियां, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त ढांचागत विकास माध्यमिक क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योगों से लाभ हुआ, संवेदी सूचकांक में उछाल भी आया, पर रोजगार के अवसरों में अपेक्षाजनक बदलाव नहीं हुआ। सरकारी मुहिम 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद बेचने के उद्देश्य से यहां उद्योग लगा रही पर ये युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। भारत में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर लघु सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग सृजित करते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, देश में लघु एवं मध्यम उद्योग कुल चालीस फीसद रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इन क्षेत्रों को भी सरकारी नीतियों से अपेक्षाजनक प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा साठ फीसद श्रमशक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में है। वर्तमान समय में देश में रोजगार की दर चालीस फीसद है। यानी यहां पर सौ लोगों में से सिर्फ चालीस लोगों के लिए काम उपलब्ध है, बाकी साठ लोगों के पास कोई काम नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में आर्थिक विकास तेजी से आगे। आगे बढ रहा है, तो रोजगार के स्रोत क्यों घट रहे हैं। देश में रोजगार की उपलब्धता कम होने से प्रतिभा संपन्न युवाओं का अन्य देशों में पलायन होने लगता है, जो देश के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में जरूरी है। कि एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर रोजगार सृजन, आर्थिक समानता लाने और प्रतिभा संपन्न युवाओं की श्रमशक्ति का सदुपयोग करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएं।

क्या ट्रंप टैरिफ वापस लेंगे?

'एप्पल' ने भारत से 67,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 'अमेजन' ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 'गूगल' ने 22-23,000 करोड़ रुपए बनाए हैं और 'मेटा' ने भी लगभग इतनी ही कमाई की है। ये सभी अमरीकी कंपनियां हैं और भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है। भारत में इनके प्लांट भी सक्रिय होंगे अथवा स्थापित होने की प्रक्रिया में होंगे! ऐसी कई और अमरीकी कंपनियां होंगी, जो भारत में व्यापार कर रही हैं और मोटा मुनाफा कूट रही हैं। इन कंपनियों के सबसे अधिक ग्राहक और उपयोगकर्ता भी भारत में हैं। यह मुनाफा अमरीका में ही जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं? चूंकि अमरीकी कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं और माल अमरीकी बाजार में जा रहा है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन उत्पादों पर भी 50 फीसदी टैरिफ थोपेंगे? बल्कि ट्रंप हररोज टैरिफ पर सफाई दे रहे हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप 100 दिनों के अंतराल में टैरिफ पर पुनर्विचार कर अपने फैसले को वापस ले सकते हैं, लिहाजा उन्होंने सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया है कि वह टैरिफ मामले पर यथाशीघ्र सुनवाई कर उसे 'वैध' करार दे। अदालत नवंबर माह में सुनवाई शुरू करेगी, यह पहले से ही तय है। राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी चिंतित हैं, क्योंकि दुनिया दो ध्रुवों के बीच बंटती जा रही है और अमरीका को 'शीत युद्ध' एक बार फिर शुरू होने की आशंका है। अमरीका की ताकत भी बंटती जा रही है। अब देश अमरीका की 'दादागीरी' मानते रहने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और अमरीकी मंत्री अब भी भारत को अपना 'परम मित्र' मानते हैं। अमरीकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश के राष्ट्रपतियों ने दशकों की मेहनत, कूटनीति, दूरदर्शिता और देशों की लामबंदी के जरिए जो ताकत अर्जित की थी और अमरीका को सबसे बड़ी 25 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया था, राष्ट्रपति ट्रंप उस पर पानी फेर रहे हैं। भारत को 50 फीसदी टैरिफ से अमरीका ने दबाव में लाने की रणनीति बनाई, लेकिन भारत दूसरे धुरव पर रूस और चीन के साथ मिल गया।

उसके समर्थन में 50 अन्य देश, ब्रिक्स और एससीओ के देश आ खड़े हुए। भारत के वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि भारत का ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ व्यापार का करार शीघ्र ही होने जा रहा है। भारत की 50 अन्य देशों के साथ भी निर्यात की संभावनाओं पर बातचीत जारी है। अमरीका के साथ भी नवंबर तक व्यापार-समझौता होना लगभग तय है। भारत आगामी दो सालों के भीतर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप को भारत से दिक्कत है अथवा रूस और चीन से? भारत ने पलट कर अमरीका पर कोई टैरिफ नहीं थोपा है। अमरीकी कंपनियां भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों से अरबों डॉलर के करार कर रही हैं। अमरीकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे अधिकारी ने अमरीका में मंदी की संभावनाओं को लेकर राष्ट्रपति को सचेत किया है। ऐसे भी विश्लेषण सामने आए हैं कि एक-तिहाई उद्योग पहले से ही आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ कारोबार कम क्यों किया जा रहा है? टैरिफ का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि रूस के साथ भारत, चीन के अलावा अमरीका और यूरोपीय देश भी तेल और गैस का धंधा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को आरोप लगाने की अपनी आदत को सुधारना चाहिए।

युवाओं को कुशल-सशक्त बनाने के उपाय

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विदेशी भाषाओं और अंतर-सांस्कृतिक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करें। युवाओं को नेतृत्व कार्यक्रमों, वाद-विवादों, आदर्श संयुक्त राष्ट्र संघों और नीति-निर्माण कार्यशालाओं में प्रशिक्षित करें। यदि इन कदमों का पालन निरंतरता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और युवा भागीदारी के साथ किया जाए, तो बेहतर होगा

'हिमालय की बर्फीली पहाडियों के बीच देवदार के पेड़ की तरह खड़े हिमाचल के युवा' राज्य की प्रगति और विकास की रीढ़ हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज 'हिमाचल प्रदेश में युवा: 2018' के अनुसार युवाओं की हिस्सेदारी राज्य की कुल जनसंख्या का 35.25 फीसदी है। युवा जनसंख्या 1971 में 10.56 लाख से बढक़र 2011 में 24.20 लाख हो गई है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल स्थानीय संघर्षों में भाग लिया, बल्कि महान नेताओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलनों में भी शामिल हुए। महात्मा गांधी के ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार के आह्वान पर हिमाचल के कई युवा असहयोग आंदोलन (1920-22) में शामिल हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैलियां आयोजित कीं, जागरूकता फैलाई और यहां तक कि कारावास का सामना भी किया। सुकेत (मंडी क्षेत्र) में, युवा नेताओं ने आम लोगों के अधिकारों और न्याय की मांग करते हुए सुकेत सत्याग्रह (1948) शुरू किया।

बुशहर, क्योंथल और चंबा जैसे राज्यों में प्रजा मंडल आंदोलनों का नेतृत्व ज्यादातर युवा कार्यकर्ताओं ने किया, जिन्होंने भारी कराधान और जबरन मजदूरी के खिलाफ किसानों को संगठित किया। डा. यशवंत सिंह परमार (जो बाद में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने) जैसे युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी राजनीति में गहराई से शामिल थे और उन्होंने लोगों को आजादी के लिए संगठित किया। हिमाचली युवा अपनी बहादुरी और सशस्त्र बलों में सेवा के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, कई पूर्व सैनिकों और सेवारत युवाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया, प्रशिक्षण दिया और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज (आईएनए) में भी शामिल हुए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (अप्रैल-जून 2025) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगारी दर 29.6 फीसदी दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 14.6 फीसदी से काफी अधिक है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 29.1 फीसदी और शहरी बेरोजगारी दर 31.3 फीसदी है। लिंग के आधार पर भी असमानताएं स्पष्ट हैं: शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर 41.2 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के लिए यह 24 फीसदी है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में 2012 और 2023 के बीच 340 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश प्रभावित व्यक्ति 15-30 वर्ष की आयु के हैं। सिंथेटिक ओपिओइड 'चिट्टा' युवाओं के बीच विशेष रूप से व्यापक हो गया है- सस्ता, अत्यधिक नशीला और स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव। दो संस्थाओं, नामत: एनआईएमएचएएनएस और एनएचएम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10-24 वर्ष की आयु के युवाओं में से 15.54 फीसदी अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं। पारंपरिक पहाड़ी बोलियों और सांस्कृतिक प्रथाओं में गिरावट आ रही है, जिसका आंशिक कारण युवाओं का शहरी केंद्रों की ओर पलायन और दस्तावेजीकरण का अभाव है।

हिमाचल प्रदेश को अपने युवाओं को बेहतर ढंग से जोडऩे के लिए पर्यटन, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, सतत कृषि, हस्तशिल्प जैसे विविध आजीविका क्षेत्रों को अपनाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर, मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशा तस्करों की पहचान करने में मदद करने का आग्रह किया है। राज्य के हरित ऊर्जा अभियान के तहत, युवाओं को आदिवासी क्षेत्रों सहित 40 फीसदी तक की सब्सिडी के साथ सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नवीकरणीय क्षेत्र में युवा उद्यमियों के लिए ब्याज सब्सिडी भी निर्धारित की गई है। युवा आपदा मित्र योजना ने 1500 युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। हाल ही में एक भर्ती अभियान के तहत 20-30 आयु वर्ग के युवाओं के लिए माइनिंग गार्ड के 80 पद खोले गए, जिसका उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना है। हिमाचल प्रदेश ने 32वीं बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 की मेजबानी की, जिसमें 22000 से अधिक छात्र और 8000 शिक्षक शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य सरकार को और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में एआई, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, रोबोटिक्स और जलवायु अध्ययन को शामिल करें।

दोहरे तोहफों की दीपावली

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के साथ जो वायदा किया था, वह साकार होने की प्रक्रिया में है। वाकई इस बार दीपावली और अन्य त्योहारों पर 'दोहरा तोहफा' मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 'सुधारों के उपहार' को स्वीकृति दे दी है। अब 22 सितंबर के बाद से आम आदमी, महिलाएं, पुरुष, युवा और औसत घर लाभान्वित होंगे। इस तारीख से 'शारदीय नवरात्र' भी आरंभ हो रहे हैं। सभी का मासिक खर्च कम होगा, तो बचत बढ़ेगी। वह बचत बाजार और औसत खपत में खर्च होगी। इससे एफएमसीजी (तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं), खुदरा और ऑटोमोबाइल आदि कई क्षेत्रों में घटे दामों पर उपभोक्ता-मांग में बढ़ोतरी होगी। विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्रों में वृद्धि होगी। मांग और खरीद बढ़ेगी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अंततः देश की अर्थव्यवस्था ही फलेगी-फूलेगी। रोटी, कपड़ा और घर के रोजमर्रा के सामान पर कर (जीएसटी) 12 फीसदी से घट कर 5 फीसदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर कर 28 फीसदी से घट कर 18 फीसदी हो जाएगा, तो यकीनन आम आदमी राहत महसूस करेगा। महंगाई पहले से ही नियंत्रण में है। यदि प्रधानमंत्री रोजगार के मोर्चे पर भी स्पष्ट योजनाओं की घोषणा कर दें, तो यह देश और भी संपन्न होगा। यदि देश संपन्न होगा और खर्च का माद्दा बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था भी व्यापक होगी और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वैसे जर्मनी और भारत की अर्थव्यवस्था के बीच बहुत कम फासला

शेष है, लिहाजा हमारा तीसरी 'आर्थिक महाशक्ति' बनना तय है। जीएसटी 2.0 सुधारों के तौर पर आठ लंबे सालों के बाद 'ऐतिहासिक बदलाव' है। उसकी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, नतीजतन करोड़ों व्यापारी और खुदरा-व्यवसायी लाभान्वित होंगे। अब कारोबारियों को टैक्स से जुड़े नियमों और कानूनों पर कम खर्च करना पड़ेगा। वे ग्राहक और नवाचार पर अधिक फोकस कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि देश में कर घटाने से 2 लाख करोड़ रुपए तक की खपत बढ़ सकती है।

इसका फायदा छोटे उद्यमों को ज्यादा होगा। आम आदमी और ग्राहकों को मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसी विपक्ष-शासित राज्यों की सरकारों ने करीब 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का मुद्दा उठाया है, लिहाजा केंद्र सरकार से मांग की है कि 5 साल तक मुआवजा दिया जाए और वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इसमें राजनीति भी हो सकती है। बहरहाल इस मुद्दे पर पर्याप्त विमर्श हुआ होगा! सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैंसर समेत 33 जीवन-रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अन्य सभी दवाओं पर अब जीएसटी 12 फीसदी से घट कर 5 फीसदी हो जाएगा। शिक्षण सामग्रियों में नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, कॉपी, नोटबुक और इरेजर आदि 12 फीसदी और 5 फीसदी से घटा कर 'शून्य जीएसटी' वाले वर्ग में डाल दिए गए हैं। इनके अलावा, हेयर ऑयल, शैंपू, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम, जिम, सैलून, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया है। बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स, प्री-पैक नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, बच्चों के नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, हैंडीक्राफ्ट आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से 5 फीसदी किया गया है। अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध, छेना, पनीर, रोटी और खाकरा, परांठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी पर जीएसटी अब 5 फीसदी के बजाय शून्य लगेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा 18 फीसदी से घटा कर शून्य किया गया है। हालांकि उपकरणों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। बीमा की दरें अब बहुत कम हो जाएंगी। देश में अभी 57 करोड़ से अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य और करीब 31 करोड़ के पास जीवन बीमा है। कृषि, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। हालांकि 40 फीसदी का एक और स्लैब रखा गया है, जो सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा आदि विलासिता की वस्तुओं के लिए होगा। इस वर्ग में 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक और निजी विमान भी शामिल हैं। जीएसटी 2.0 से हाथों में सीधे पैसे आएंगे, नतीजतन भारत वैश्विक निर्यात का मजबूत केंद्र बनेगा। हालांकि यह भी सच्चाई है कि आर्थिकी के क्षेत्र में भारत को अभी अमरीका व चीन जैसे देशों की तुलना में

स्टेटस का चक्कर

विजय गर्ग

गोस्वामी जी ने जब सरकारी दफ्तर से सेवानिवृत्ति ली तो उनका जीवन एक साधारण, व्यवस्थित दिनचर्या का आदर्श नमूना था। सुबह छह बजे की चाय, फिर अख़बार, दोपहर में पत्नी से हल्की-फुल्की बहस, और शाम को मोहल्ले की बेंच पर बैठकर दुनिया भर की समस्याओं पर ' अंतिम निर्णय' देना । जीवन का हर पृष्ठ, मानो, तयशुदा क़ानूनों के अनुसार पलटा जा रहा था।

किंतु, जब उनके बेटे ने एक स्मार्टफोन नामक 'जादुई डिब्बा' उनके हाथ में रख दिया, तो गोस्वामी जी के जीवन की पूरी व्यवस्था डगमगा गई। पहले तो उन्हें लगा कि यह केवल बात करने और ख़बरें पढ़ने का एक यंत्र है । पर जल्द ही उन्हें 'सोशल मीडिया' नामक एक विचित्र संस्था का ज्ञान हुआ, जहाँ लोग अपनी पसंद और नापसंद को दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं, और बदले में, दूसरों की पसंद-नापसंद पर अपनी मुहर लगाते हैं। उन्होंने उत्सुकतावश अपनी बालकनी में लगे गमले की तस्वीर खींचकर डाल दी, और नीचे लिखा, आज का मौसम बहुत सुहाना है। अगले कुछ घंटों में तीन 'लाइक' आए। गोस्वामी जी के लिए यह केवल तीन लोगों की पसंद नहीं थी, बल्कि यह तीन व्यक्तियों का एक ऐसा प्रमाण-पत्र था कि उनका अस्तित्व और उनकी भावनाएँ, इस विशाल संसार में, मायने रखती हैं।

अब गोस्वामी जी का जीवन, 'लाइक' की खेती में बदल गया था। उनका दार्शनिक मन यह समझने में लगा था कि आखर किस प्रकार की पोस्ट पर ज़्यादा' फसल' उगती है। उन्होंने पाया कि जो तस्वीर वे पूरे मन से लेते हैं, जैसे कि किसी पुरानी किताब की, उस पर इक्का-दुक्का लाइक आते हैं। मगर, अगर वे अधखाए समोसे की तस्वीर खींचकर, अहो ! समोसा ! लिख दें, तो 'फसल' दोगुनी हो जाती है। यह एक ऐसा वैज्ञानिक विरोधाभास था, जिसने उनकी जीवनभर की समझ को चुनौती दी । यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान और कला की तुलना में, पेट और बाज़ार का दर्शन अधिक प्रभावी है। उन्होंने इस नए विज्ञान को आत्मसात कर लिया और हर पोस्ट के साथ 'स' नामक एक धार्मिक मंत्र का जाप करने लगे, जिसे लगाने से, उनकी पोस्ट, बिना किसी कारण, हज़ारों लोगों की पवित्र दृष्टि तक पहुँच जाती थी ।

कुछ ही महीनों में, गोस्वामी जी की सारी दुनिया स्क्रीन के भीतर समा गई थी। सुबह की चाय, अख़बार का सब्ज़ी बेचना, पत्नी की डाँट, सब अब 'कंटेंट' था। पत्नी अगर किसी बात पर नाराज़ होकर ऊँची आवाज़ में बोलती तो वे तुरंत कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगते। उनका तर्क था, अगर कोई फ़िल्मकार परिवार की समस्याओं पर 'सीरियल' बना सकता है, तो हम अपनी समस्याओं का 'रियल' क्यों नहीं बना सकते ? उनके लिए अब परिवार एक परिवार नहीं, बल्कि एक दर्शक - समूह था, और घर एक 'शूटिंग लोकेशन'। अपने हर अनुभव को कैमरे की आँख से देखने लगे थे। जीना कम, जीकर दूसरों को दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया।

सोशल मीडिया का सामाजिक नियम- शास्त्र, किसी भी सरकारी विभाग से ज़्यादा जटिल निकला। यहाँ' फॉलो' का अर्थ था 'अनुदान', और 'लाइक' का अर्थ था 'मंजूरी ।' यदि कोई आपको फॉलो करता है तो यह आवश्यक था कि आप भी उसे फॉलो करें, अन्यथा 'संबंध-विच्छेद' का नोटिस आ सकता था। सबसे बड़ा संकट था 'नकारात्मक टिप्पणी' का। किसी अजनबी ने एक बार लिख दिया, अंकल, फ़ोटो क्लियर नहीं है । गोस्वामी जी के लिए यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक अपमान था, एक ऐसी चोट जिसका घाव कोई सरकारी फाइल भी नहीं दे सकती थी । उन्होंने तुरंत साइबर क़ानून की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि इस अपराधी को खोज सकें।

धीरे-धीरे, उनके 'फॉलोवर्स' की संख्या बढ़ती गई। सौ से हज़ार, हज़ार से दस हज़ार उन्हें' इन्फ्लुएंसर' कहा जाने लगा । अब उन्हें कई कंपनियों से 'सहयोग' के प्रस्ताव आने लगे, जिसमें एक कंपनी ने उन्हें मुफ्त में एक कलम देने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे उसकी तारीफ़ करें । गोस्वामी जी का सीना गर्व से फूल गया। उन्हें लगा कि वे अब केवल एक सेवानिवृत्त बाबू नहीं, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे रात-दिन अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में लगे रहते, और इस बात का ध्यान रखते कि कोई भी उनकी 'ऑनलाइन छवि' पर उँगली न उठा पाए ।x

एक दिन, पूरे शहर का इंटरनेट अचानक बंद हो गया । गोस्वामी जी के हाथ से मानो उनका जीवन- सार छिन गया । स्क्रीन काली थी, और कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे उनका अस्तित्व ही मिट गया हो। उन्होंने निराशा से चारों ओर देखा ।

पत्नी बैठी हुई ऊन का गोला बना रही थी, दीवार पर लगी घड़ी की टिकटिक सुनाई दे रही थी, और कमरे में एक अजीब-सी खामोशी थी। उन्हें लगा, ये सब कितना बेमानी है। जब तक कोई इसे 'लाइक' नहीं करता, तब तक इसका क्या मूल्य ? जब इंटरनेट वापस आया, तो उन्हें यह सब कुछ, एक पल में, निरर्थक लगा, और वे तुरंत अपने 'डिजिटल जीवन' में लौट गए।

आज गोस्वामी जी अपने क्षेत्र के एक 'सफल' व्यक्ति हैं। उनके कई हज़ार अनुयायी हैं, और वे हर सुबह 'सुबह मुबारक' का स्टेटस अपडेट करते हैं। उनके पास अब हज़ारों डिजिटल मित्र हैं, जिनसे वे कभी मिले नहीं, और कुछ ही वास्तविक मित्र हैं, जिनसे वे अब बात नहीं करते। उनका जीवन, एक ऐसे मंच पर एक नाटक बन गया है, जो हकीक़त में मौजूद नहीं है। और इस नाटक में वे इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं कि असली

पृथ्वी का धीमा रोटेशन वायुमंडल में ऑक्सीजन के उदय की व्याख्या कर सकता है

विजय गर्ग

हाल के शोध में पृथ्वी के धीमे रोटेशन और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन के उदय के बीच एक कड़ी का सुझाव दिया गया है, विशेष रूप से ग्रेट ऑक्सीकरण इवेंट और नियोप्रोट्रोज़ोइक ऑक्सीकरण घटना के दौरान। इस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि जैसे-जैसे दिन-रात चक्र लंबा होता गया, इसने ऑक्सीजन पैदा करने वाले रोगाणुओं के लिए अधिक अनुकूल स्थिति पैदा की। लिंक के पीछे तंत्र साइनोबैक्टीरिया पर पृथ्वी के रोटेशन और ऑक्सीजन के स्तर केंद्रों के बीच संबंध, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रारंभिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन के प्राथमिक उत्पादक थे। इस तंत्र के प्रमुख पहलू हैं:

लंबे समय तक ₹ऑक्सीजन विंडोज₹: साइनोबैक्टीरिया में सूर्योदय के बाद ₹वार्म-अप₹ अवधि होती है, इससे पहले कि वे कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर सकें। कम दिनों के साथ तेजी से कताई, प्रारंभिक पृथ्वी पर, उत्पादन में इस अंतराल का मतलब था कि कम समग्र ऑक्सीजन जारी की गई थी। जैसे-जैसे पृथ्वी का घूमना धीमा होता गया, दिन लंबे होते गए, इन रोगाणुओं को प्रकाश संश्लेषण और अधिक ऑक्सीजन छोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की एक विस्तारित खिड़की मिलती गई।

अन्य रोगाणुओं के साथ प्रतिस्पर्धा: शुरुआती माइक्रोबियल मैट में - सूक्ष्मजीवों के घने, स्तरित समुदाय - ऑक्सीजन उत्पादक सायनोबैक्टीरिया अन्य रोगाणुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि सल्फर का उपभोग करने वाले। कम दिनों के दौरान, सल्फर खाने वाले रोगाणुओं दिन के एक बड़े हिस्से के लिए हावी हो जाएगा, ऑक्सीजन का उत्पादन और निर्यात करने की साइनोबैक्टीरिया की क्षमता को सीमित करता है। लंबे समय तक सायनोबैक्टीरिया को अधिक निरंतर अवधि के लिए प्रकाश संश्लेषण करने की अनुमति दी गई, अन्य रोगाणुओं को मात दी और पर्यावरण में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक शुद्ध रिहाई को सक्षम किया।

बढ़ा हुआ प्रसार: एक लंबे दिन-रात चक्र ने माइक्रोबियल मैट के भीतर उत्पादित ऑक्सीजन के लिए अधिक समय की अनुमति दी ताकि आसपास के पानी में फैल सके और अंततः, वातावरण में। छोटे दिनों के साथ, ऑक्सीजन मैट के अंदर निर्माण होगा, लेकिन रात के गिरने से पहले बचने के लिए कम समय है। पृथ्वी का धीमा रोटेशन पृथ्वी का घूमना धीरे-धीरे अरबों वर्षों से धीमा हो रहा है, मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पुल के कारण होने वाले ज्वारीय घर्षण से प्रेरित एक प्रक्रिया है। यह घर्षण ग्रह के स्पिन पर एक ₹ब्रेकर₹ बनाता है, धीरे-धीरे लंबे समय तक थोड़ी मात्रा में दिन को लंबा करता है। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के साक्ष्य इंगित करते हैं कि पृथ्वी के शुरुआती दिन 6 घंटे कम थे। यह निरंतर मंदी और परिणामस्वरूप लंबे दिन एक महत्वपूर्ण, पहले अनदेखी कारक हो सकते हैं जिसने पृथ्वी के वायुमंडल को अपनी वर्तमान ऑक्सीजन युक्त स्थिति की ओर धकेलने में मदद की।

माणकी -मुंडा शहिदों को श्रद्धांजलि देने गुआ नहीं जायेगें , चाईबासा मे देगें: अमृत मांझी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

चाईबासा , पश्चिमी सिंहभूम एवं जिला प्रशासन और मानकी मुण्डा संघ के बीच खटास बढ़ने के कारण माणकी-मुंडा- डाकुआ संघ कोल्हान पोड़ाहाट द्वारा आगामी आठ सितंबर गुआ गोलीकांड पर शामिल नहीं होने का मन बनाया है । कल माणकी मुंडाओं का जत्था कमिश्नरी मुख्यालय चाईबासा बस स्टैंड के पास विरसा मुंडा स्टेच्यू पर गुआ शहिदों को श्रद्धांजलि देगा । इसी बीच जिला प्रशासन ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में माणकी मुंडाओं संग प्रशासन का हमेशा से एक मजबूत और परस्पर धनिष्ठा की रिश्ता रही है । पर आज सोशल मिडिया पर बात को तोड मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ।आगे प्रशासन ने कहा है आज जिला और कोल्हान क्षेत्र में विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा हैं। इस संबंध का मूल उद्देश्य आदिवासियों का समग्र विकास करना और जिला प्रशासन तथा जिले के निवासियों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करना उद्देश्य है।

भारतीय संविधान का पांचवीं अनुसूची में दर्ज इलाका जहां केवल पूर्वोत्तर भारत ही नहीं वल्कि पश्चिमी सिंहभूम भी निहित है ।यहां विगत कुछ समय से विलकिंसन रूल समय से पदस्थापित माणिकी मुंडाओं के साथ जिला प्रशासन मधुरता में कमी होने की आवाज नेताओं द्वारा सुनाई पड़ रही है । जिसपर आज जिला प्रशासन की तरफ से उस वैमनस्यता को दुर करने हेतु कदम उठाया गया है ।

पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मानकी और मुंडा राजस्व प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं और वंशावली इन्हीं के द्वारा निर्गत की जाती है। यह परंपरा पूर्ववत कायम रहेगी। जहां किसी कारण से मुंडा के स्तर से वंशावली निर्गत होना संभव नहीं हो पा रहा है (जैसे- मुण्डा की मृत्यु होना या अनुपस्थिति इत्यादि) वहां मानकी द्वारा वंशावली निर्गत करने की परंपरा बनी रहेगी। यदि दोनों ही उपलब्ध नहीं हों, तो पूर्व की भांति परम्परागत रूप से क्रियान्वित विकल्पों से वंशावली निर्गत की जाएगी।

कुशल प्रशासन एवं लोकहित को सर्वपरि रखते हुए जिलान्तर्गत विगत दो-तीन माह में तेजी से रिक्त मुण्डा-मानकियों के पद पर ग्राम सभा के माध्यम से नियुक्ति की गयी है। शेष रिक्त पदों पर भी ग्रामसभा कर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी।

जिला प्रशासन यह स्पष्ट करता है कि किसी मानकी-मुण्डा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर कोल्हान अधीक्षक अथवा मुंडा-मानकी न्याय पंच द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। जांच प्रतिवेदन में शिकायत प्रमाणित होने पर ही नियमानुसार मुंडा / मानकी को पद विमुक्त किया जा सकेगा।

विगत दिनों में यह भी पाया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया, इत्यादि के माध्यम से मुण्डा के पद विमुक्त किये जाने के संदर्भ में भ्रामक तथ्य फैलाकर समाज में शांति भंग किया जा रहा है। इससे जिला प्रशासन की छवि धुमिल हो रही है एवं मानकी-मुण्डा के मानसपटल में असंतोष का बीजारोपण हो रहा है। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त न्यायालय में मानकी-मुण्डा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के आलोक में वर्त्तमान में किसी मानकी-मुण्डा को पद विमुक्त नहीं किया गया है। अतः सूचित किया जाता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुण्डा-मानकी पद विमुक्ति इत्यादि के संदर्भ में भ्रामक तथ्य फैलाये जाने की पुनर्रावृति किये जाने पर उन्हें चिन्हित कर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

मुण्डा-मानकी न्याय पंच द्वारा पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि कोल्हान क्षेत्र / जिला के निवासियों को हुकुकनामा, विलकिन्सन रूल्स तथा अन्य नियमों के संदर्भ में समुचित जानकारी का अभाव है। अतः इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में आम निवासी /मुंडा/मानकी को उपरोक्त के आलोक में अपने दायित्वों एवं अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। प्रशासन द्वारा गुआ गोलीकांड दिवस पर परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में आने का निमंत्रण की गयी है । उधर आदिवासियों की तरफ से जुझारू नेता अमृत मांझी एवं उनके सहयोगियों ने कहा कि कल गुआ हमलोग नहीं जायेंगे शहिदों को श्रद्धांजलि चाईबासा में देगें ।

जीएसटी 2.0 : आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम

प्रो. महेश चंद गुप्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर किए वादे को पूरा करते हुए दिवाली से पहले सरकार ने जनता को जीएसटी सुधार के रूप में ऐसा तोहफा दिया है, जो न सिर्फ आम जन के जीवन को सरल बनाएगा बल्कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को और मजबूती से धरातल पर उतारेगा। जीएसटी 2.0 केवल टैक्स सुधार नहीं बल्कि भारत की अगली आर्थिक यात्रा का मानचित्र है। जहां देशवासी खुश हैं, वहीं इस सुधार में गहरा अंतरराष्ट्रीय संदेश भी निहित है। यह सुधार अमेरिका द्वारा लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ का उत्तर भारत ने अपनी आर्थिक मजबूती और आत्म निर्भरता के रूप में दिया है।

जीएसटी सुधार से किसान, महिला, युवा, मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी और उपभोक्ता सभी लाभान्वित होंगे। यह कदम केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास मात्र नहीं है बल्कि भारत को एक तेज, सशक्त और आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। यह सुधार जितना घरेलू स्तर पर आम लोगों को राहत देगा, उतना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सशक्त छवि को भी मजबूत करेगा।

बदलावों की जरूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखांकित किया है। मोदी ने कहा है कि अगर भारत को वैश्विक परिदृश्य में उचित स्थान दिलाना है तो समय-समय पर बदलाव बेहद जरूरी हैं। यह सुधार देश को सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज देंगे। गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं, छात्रों, किसानों और नौजवानों को इसका सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया है कि यह सुधार सिर्फ टैक्स में बदलाव नहीं है, बल्कि आत्म निर्भर भारत के लिए अगली पीढ़ी का सुधार है।

सरकार ने आनन-फानन में यह फैसला नहीं किया है बल्कि उसने इस सुधार में सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा है। तम्बाकू उत्पादों, सिगरेट, शराब, महंगी कारों, विमान आदि पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है पर इसका सीधा असर अमीर वर्ग पर पड़ेगा जबकि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा असर यह होगा कि उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा और घरेलू खपत में इजाफा होगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब खपत बढ़ेगी तो उत्पादन और व्यापार का दायरा भी बढ़ेगा। कंपनियां अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्थिति में होंगी जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रकार जीएसटी सुधार और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना मिलकर अर्थव्यवस्था को गति देंगे। उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलेगा और युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह संतुलन अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक विकास दोनों को साथ लेकर चलेगा।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। इसने 17 केंद्रीय और राज्य करों को हटा कर 'एक राष्ट्र एक कर' लागू कर देश में सामान्य राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया। आठ वर्षों में जीएसटी लगातार विकसित हुआ है और अब डिजिटलीकरण तथा दर युक्तिकरण के जरिये यह भारतीय कर व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। अर्थव्यवस्था के तेजी से बदलते स्वरूप को देखते हुए टैक्स प्रणाली को सरल और व्यवहारिक बनाना आवश्यक हो गया था। सरकार ने इसी जरूरत को समझते हुए जीएसटी 2.0 के रूप में एक ऐसा सुधार सामने रखा है जो व्यापक दृष्टिकोण से सोचा-समझा और जन हितैषी है। जीएसटी 2.0 में सबसे बड़ा परिवर्तन टैक्स स्लैब की संख्या घटाना है। पहले चार प्रमुख दरें थीं यानी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। अब इन्हें घटाकर सिर्फ दो कर दिया गया है। जरूरी सामानों पर 5 प्रतिशत और सामान्य वस्तुओं पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

क्या श्रीमंदिर सरकारी खेल का मैदान है? गंभीर अनियमितताएँ कि साथ संपत्ति लूटी गई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर:- कांग्रेस भवन में कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता जयश्री पात्रा ने पास वितरण में हुई अनियमितताओं पर गंभीर जानकारी पेश की।

प्रवक्ता श्रीमती पात्रा ने बताया कि पिछली 2025 रथ यात्राओं से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, 2500 घेरा पास और 22,500 अन्य पास, कुल 24,350 पास वितरित किए गए, जो पिछली बीजद सरकार द्वारा वितरित 5000 पास से लगभग पाँच गुना अधिक है। श्रीमती पात्रा ने कानून मंत्री से स्पष्टीकरण माँगा है कि इतनी बड़ी संख्या में वीआईपी पास वितरित करने में किसका हित निहित था, जबकि आम जनता को दर्शन के लिए कष्ट सहना पड़ा।

जो पार्टी विपक्ष में रहते हुए श्रीमंदिर में कतारों के खिलाफ शोर मचाती थी, उसने सत्ता में आते ही कतारें लागू कर दी हैं। काफी विवाद के बाद संचालन समिति का गठन तो हुआ, लेकिन वह किसी पार्टी समिति जैसी ही लगती है। समिति ने दर्शन को प्राथमिकता दी है। लेकिन दर्शन इतना आसान नहीं है। रथ यात्रा के दौरान बैरिकेड्स, राधा माधव बीजे, वृद्ध माता हविश्याली का कतार में खड़ा होना, भीड़ का महास्ना, भोग में व्यवधान आदि जैसी समस्याएँ दर्शन के दौरान पैदा होंगी। श्रीमती पात्रा ने पूछा कि क्या समिति इस पर नज़र रख रही है।

पीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक, ललातेन्दु दास ने चौंकाने वाली जानकारी साझा की कि कैसे सुबह के समय श्रीमंदिर की खदानों को लूटा जा रहा है। महाप्रभु के पास पूरे भारत में 62 हज़ार करोड़ रुपये की संपत्ति है और इसमें से, सभी जानते हैं कि 38 हज़ार करोड़ रुपये ओडिशा में हैं। हालाँकि, ओडिशा में लगभग 30% संपत्ति अकेले खोरधा और पुरी में है। इस संपत्ति में हजारों करोड़ रुपये की रेत, मोरम और मनकड़ा पत्थर की खदानें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय से इस खदान की नीलामी नहीं की है, लेकिन नीलामी न होने के बावजूद, प्रभावशाली लोग सरकार की छत्रछाया में खदान को लूटते रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले मई में, उच्च न्यायालय द्वारा गठित पीठ के अध्यक्ष, माननीय न्यायमूर्ति संजीब पाणिग्रही ने कहा था कि महाप्रभु की पहचान की सुरक्षा में अपवाद न केवल एक कानूनी समस्या है, बल्कि आध्यात्मिक अपमान और सांस्कृतिक क्षति भी है और उन्होंने निर्देश दिया था कि सरकार तुरंत महाप्रभु की संपत्ति वापस ले। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के चार महीने बाद भी, सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है।

प्रवक्ता श्री दास ने कानून मंत्री से आग्रह किया है कि या तो वे कहें कि महाप्रभु की संपत्ति कानून मंत्री के परिवार के कब्जे में है या फिर यह बयान दें कि परिवार के पास कब्जा नहीं है।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व वित्त मंत्री पंचानन कानूनगो ने जीएसटी पर अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया सेल के अध्यक्ष अरविंद दास, प्रवक्ता रजनी मोहंती और लालतेंदु दास भी उपस्थित थे।

प0 सिंहभूम में दस लाख ईनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अपटन मुठभेड़ में ढेर

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची, पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा की आराहासा पंचायत के रेलापराल गांव के पास रविवार सुबह मुठभेड़ हुई। यहां की बुरजूवा पहाड़ी पर आज भोर हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दस लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया गया है।

मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से एक एसएलआर राइफल और कई अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है, ताकि किसी छिपे हुए नक्सली को पकड़ा जा सके। यह कार्रवाई एक खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। चाईबासा एसपी को सूचना मिली थी कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र की आराहासा पंचायत के रेलापाराल गांव के पास कुछ नक्सली इकट्ठा होकर किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं।

सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया। जैसे ही जवान गांव के पास पहुंचे, नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और कार्रवाई की, जिसमें अमित हांसदा मारा गया। उसकी मौके पर ही पहचान हो गई। वह लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था और कई हिंसक घटनाओं में शामिल था।

ग़रीबी ऐसी की झारखंड में अपने बच्चे को बाप ने महज पचास हजार में बेचा

मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर बरामद करवाया , परिवार मूलत उत्तर प्रदेश का, जिसे तत्काल 20 किलो अनाज दिलवायी गयी

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची , आज से बीस -बाईस साल पहले पश्चिम ओडिशा से मानव बच्चे बेचने का खबर देश को स्तब्ध कर दिया था । उन दिनों मामला तब गर्म हुआ जब एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के पत्रकारों ने बच्चों को खरीद कर दिल्ली ले गये फिर मामला गरम हुई , शर्मशार करने वाली घना पर तब जाकर रोक लगी । पर आज देश का एक समृद्ध राज्य झारखंड जहां में गरीबी के चलते एक महीने के बच्चे को उसके पिता ने 50 हजार रुपये में बेच दिया था ।पर मामला सामने आते ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सीएम ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चे को बरामद कर लिया गया ।यह घटना पलामू जिले के लेस्लीगंज क्षेत्र की है । लेस्लीगंज सर्किल ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दंपति ने गरीबी के चलते अपने नवजात बेटे को एक दूसरे दंपति को बेच दिया। मामला उजागर होते ही जिला प्रशासन ने परिवार की मदद के लिए 20 किलो राशन दिया।

अपने बच्चे को दलाल से बेचने वाले पिता ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। बच्चे के पिता रामचंद्र राम ने कहा कि मेरे पास न तो इलाज के लिए पैसे थे और न ही बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकता था। रामचंद्र ने कहा कि मेरी पत्नी पिंकी देवी बच्चे के जन्म के बाद से बीमार है। मैं कई महीनों से बेरोजगार हूं, बारिश की वजह से काम बंद है। हम सड़क किनारे टीन के छप्पर के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसलिए बच्चे को बेचने का फैसला किया।

रामचंद्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। वो बीते 15 सालों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झारखंड के लोटवा गांव में रह रहे हैं। रामचंद्र ने बताया कि वो अपने दैनिक जीवन के खर्चों के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन काम न मिलने पर भीख तक मांगनी पड़ जाती है। परिवार के पास न तो आधार कार्ड था और न ही राशन कार्ड, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है।

इस मामले पर बात करते हुए राम चंद्र की पत्नी और बच्चे की मां पिंकी देवी ने बताया कि उनके पिता ने थोड़ी जमीन दी थी, जिस पर झोपड़ी बनाई थी, लेकिन भारी बारिश में वह भी गिर गई। उन्होंने कहा कि मजबूरी में पूरा परिवार टीन के छप्पर के नीचे रहता है। वहीं, बच्चे का जन्म भी इसी छप्पर के नीचे हुआ और इसके बाद से मां बीमार चल रही थी ।लेस्लीगंज पुलिस ने मामला सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम लातेहार भेजी। वहां से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि बच्चे को सुरक्षित वापस लाने के लिए टीम काम कर रही थी।

नवीन जाएंगे दिल्ली, उपराष्ट्रपति चुनाव केलिए क्या !

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : उपराष्ट्रपति चुनाव 9 तारीख को होना है। इससे पहले, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक रविवार को चार दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नवीन के इस दौरे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। बीजेडी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए या इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का समर्थन करेगी या नहीं ।पार्टी के अंदर कई जगह इस बात पर चर्चा हो रही है कि एनडीए को समर्थन देना पार्टी के लिए कई बार महंगा साबित हुआ है। हालांकि, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का रुख बदलेगा या नहीं। बीजेडी के पास अभी 7 राज्यसभा सदस्य हैं। उनके सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, एक अलिखित आदेश जारी किया गया है कि पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। वोटिंग से इनकार करना अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के समान है। वहीं, दूसरी ओर, ऐसे में शनिवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई थी। नवीन की

अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि अगर पार्टी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करती है तो इससे बीजेडी को नुकसान होगा। बैठक में मौजूद एक सदस्य से मिली जानकारी के मुताबिक, हालांकि सभी ने अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए उम्मीदवार का विरोध करने का प्रस्ताव रखा, पीएसी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सदस्य प्रमिला मलिक ने कहा, नवीन तय करेंगे कि पार्टी का फैसला क्या होगा, जिसे लेकर बीजद के अंदर गरमागरम बहस चल रही है। अगर नवीन फैसला लेते हैं और बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तो पार्टी के अंदर कई सवाल उठेंगे कि पीएसी क्यों बुलाई गई।

झारखंड में पहली बार पैंतीस हजार सरकारी स्कूलों में शिक्षक-अभिभावकों की होगी बैठक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड सरकार 8 से 13 सितंबर तक राज्य के 35,000 सरकारी स्कूलों में द्वितीय वार्षिक शिक्षक-अभिभावक बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक का उद्देश्य 6 से 18 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना और उनकी कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी कराना है। इसके लिए माता-पिता और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को अहम माना गया है। इस बैठक में पहली बार मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, सीखने के स्तर, खेलकूद, रिजल्ट, साफ-सफाई, लाइब्रेरी तथा स्कूल कैंपस के बेहतर से बेहतर उपयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस योजना की सफलता के लिए सहयोग का आग्रह किया है। वे स्कूलों में कम नामांकन और अधिक अनुपस्थिति वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने को भी कह रही हैं। राज्य सरकार की यह पहल न सिर्फ बच्चों की शिक्षा स्तर बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनायेगी। इसके साथ ही यह कार्यक्रम बाल शिक्षा के अधिकारों की जानकारी और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस तरह की त्रैमासिक बैठकें बच्चों की पढ़ाई के लिए माता-पिता की जिम्मेदारी को समझाने एवं शैक्षिक विकास के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने में कारगर साबित होंगी। आगामी तीसरी वार्षिक अभिभावक शिक्षक बैठक दिसंबर में होगी।

श्रद्धा से जुड़ती है आत्मा – पितृ पक्ष का संदेश !

हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक मानी जाती है। इसमें धर्म, दर्शन, जीवन मूल्य, सामाजिक संरचना, पारिवारिक संबंध और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का विशेष स्थान है। भारतीय समाज में परिवार और पूर्वजों के प्रति आदर और कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया जाता है। इन्हीं मूल्यों का प्रतिबिंब हमें श्राद्ध(पितृ पक्ष) जैसे अनुष्ठानों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतनी ही श्रद्धा पूर्वजों यानी पितरों की आराधना को भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष के 16 दिनों के दौरान, पितृलोक से पितर धरती पर अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा लेकर आते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से उन्हें संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद स्वरूप अपने वंशजों को उन्नति का वरदान देते हैं। पाठक जानते होंगे कि इस साल पितृ पक्ष(श्राद्ध पक्ष) की शुरुआत 7 सितंबर 2025, रविवार से हो चुकी है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा तो वहीं पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध यानी प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को पड़ेगा और महालया श्राद्ध 21 सितंबर(सर्व पितृ अमावस्या) को रहेगा। पाठकों को बताता चलूं कि हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिनों का यह काल पितरों को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे कनागत भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य कन्या राशि में संचार करते हैं। इस वर्ष पितृ पक्ष 15 दिन का होगा।पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष माना जाता है, पर इसका आरम्भ भाद्रपद पूर्णिमा से ही होता है।वास्तव में, श्राद्ध एक धार्मिक अनुष्ठान है जो विशेष रूप से पूर्वजों (पितरों) की आत्मा की शांति और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह हिन्दू धर्म की परंपरा है, जिसमें पितरों के प्रति श्रद्धा (श्रद्धा भाव) प्रकट कर उन्हें तर्पण, भोजन, दान और प्रार्थना अर्पित की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध स्वीकार करते हैं। पितृ वास्तव में श्रद्धा के भूखे होते हैं, इसलिए इन दिनों पूरी निष्ठा से अर्पण करना चाहिए। तामसिक आहार, विवाद, क्रोध और अपमान से बचना चाहिए तथा सात्विक आचरण के साथ पितरों का स्मरण करना चाहिए। जानकारी के अनुसार पितृ पक्ष में प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्घ्य देना चाहिए और जीवन के मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। वास्तव में, जल का तर्पण अत्यंत फलदायी माना गया है। कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक किए गए श्रद्ध से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को सुख-समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए तथा घर को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। पिंडदान (यदि संभव हो) चावल, तिल, घी, शहद और दूध से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। पाठकों को बताता चलूं कि पितृ पक्ष में पिंडदान में अन्न का विशेष महत्व है। पिंडों में चावल, जौ, तिल और शहद का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि ये तत्व पंचमहाभूतों से संबंधित हैं और आत्मा को स्थिरता प्रदान करते हैं ।ज्योतिष में माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है, तो उसके जीवन में मानसिक तनाव, विवाह में विलंब, संतान सुख में बाधा या आर्थिक परेशानियाँ आ सकती हैं। श्राद्ध कर्म से इसे दूर करने की परंपरा है। पितृ तर्पण के लिए तांबे/पीतल के पात्र में जल, काले तिल, कुश, अक्षत और फूल डालने चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, कुश हाथ में लेकर

जल अर्पित करना चाहिए। 'ॐ पितृदेवाय नमः' कहते हुए तर्पण करना चाहिए ।पितृ मंत्र का जैसे 'ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः' का जप करना चाहिए तथा पितरों से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पाठकों को बताता चलूं कि पितृपक्ष में मांस-मदिरा, प्याज-लहसुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है तथा किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए तथा भोजन का कुछ भाग कौवे, कुते और गाय को अर्पित करना चाहिए। पाठकों को बताता चलूं कि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि यदि कौवा भोजन स्वीकार कर ले, तो इसका अर्थ है कि पितरों ने तृप्ति प्राप्त कर ली है। दान विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, तिल, घी और जल का होता है। माना जाता है कि यह दान पितरों तक सीधे पहुँचता है और उनके लिए शुभ फल प्रदान करता है। कहा गया है कि यह समय(पितृ पक्ष) व्यक्ति को अपने कर्मों का विश्लेषण कर जीवन की दिशा सुधारने का अवसर देता है। सच तो यह है कि पितृ पक्ष आत्म-चिंतन का भी समय है। बहरहाल, श्राद्ध के उद्देश्यों की यदि हम यहां पर बात करें तो यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, आध्यात्मिक शांति, परिवार की एकता, धार्मिक अनुशासन और हमारी सामाजिक परंपराओं को निभाकर समाज में सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में पितरों का आशीर्वाद वंश के सुख-समृद्धि का कारण माना जाता है। कहते हैं कि श्राद्ध से मन व आत्मा की शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान और अन्न अर्पण से पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर परिवार का कल्याण करती है। वास्तव में, यह अनुष्ठान मृत्यु के दुख को आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार कर जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। श्राद्ध यह सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम अपने पूर्वजों की विरासत का हिस्सा हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे दार्शनिक अर्थ जीवन और मृत्यु का स्वीकार, आत्मा की यात्रा का सम्मान,परंपरा के प्रति निष्ठा, सेवा और समर्पण का भाव आदि को उजागर करता है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत एक खास खगोलीय घटना के साथ हुई है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी ठीक उसी दिन पड़ रहा है, यानी 7 सितंबर को। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण था, जो भारत सहित कई देशों में साफ़ दिखाई दिया। ऐसे में यह संयोग धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। अंत में, यही कहूंगा कि पितृ पक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा पर्व है जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है। यह हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव जगाता है, परिवार की परंपरा और संस्कार को सुदृढ़ करता है, और आत्मा की शांति का मार्ग प्रदान करता है। यह पर्व स्मरण, सेवा, दान और आत्मचिंतन का समग्र साधन है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार

बिहार की राजनीति में आँसूओं और मुद्दों की जंग ?

प्रभुनाथ शुक्ल

बिहार की सियासत इस समय सबसे गर्म मुद्दा बन चुकी है। भाजपा और नीतीश जहां सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं, वहीं राहुल और तेजस्वी उन्हें नए नजरिए की राजनीति से सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। सत्ता और विपक्ष में शह मात का खेल जारी है। कौन किस पर भारी पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन बिहार के मतदाताओं पर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का असर पड़ता दिख रहा है। अगर ऐसा न होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आँखों से आँसू न निकलते। अब पीएम मोदी के आंसुओं का बिहार के वोटरों पर कितना असर पड़ता है यह देखना होगा लेकिन गाली -गलौज की राजनीति सभ्य लोकतंत्र के लिए दुःखद है। हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। मोदी हमारे देश के पीएम हैं। किसी भी राजनैतिक मंच से इस तरह की अमर्यादित भाषा हमारी राजनीति को गिराती है।

बिहार की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुक अपील और मां को गाली दिए जाने पर दरभंगा की रैली में चुनावी मंच से आंखें नम हो जाना भावनात्मक पॉलिटिक्स की तरफ साफ इशारा करते हैं । पीएम मोदी इमोशनल पॉलिटिक्स करते हैं। विपक्ष जिस अस्त्र से हमला करता है, मोदी उसे ही अपना अचूक हथियार बना कर विपक्ष पर पलटवार करते हैं। मोदी की चुनावी पॉलिटिक्स की यह सबसे बड़ी खूबी रही है। हालांकि जिस मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, उस मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला करने के लिए इसे ब्रह्मास्त्र के तौर पर प्रयोग किया। अब इसका कितना असर होगा, यह चुनाव परिणाम के बाद ही दिखेगा।

बिहार की पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। वह मंजे हुए राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार हैं। उनके पास जाति समूह का भारी भरकम बैंक भी है लेकिन अब उनकी उम्र राजनीति में बाधा बनती दिखती है। लम्बे वक्त से वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिसकी वजह से एंटी इनकंबेंसी दिखती है। दूसरी तरह बिहार में पलायन, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे जैसे आम सवाल हैं जिन पर नीतीश सरकार की पकड़ ढीली पड़ रही है। आंतरिक तौर पर भाजपा को भी उन पर उतना भरोसा नहीं है। क्योंकि बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन मजबूती से उभरता है तो भाजपा से दोस्ती फिर आसान नहीं होगी। दूसरी तरफ उनकी अवसरवादी राजनीति से भाजपा भी सतर्क है लेकिन चुनाव पूर्व नीतीश से रिश्तों को लेकर वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती।

राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा के जरिए सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप से भाजपा और आयोग की मुश्किल बढ़ी है। राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर भी बौद्धिक वर्ग अपनी तरफ से चिंतन कर रहा है। विश्वसनीय संस्था चुनाव आयोग पर इस तरह से उठाए गए सवाल भी लोकतंत्र की अलगियत और उसकी गरिमा कम करते हैं। आयोग अपनी पारदर्शिता पर कुछ भी कहे, लेकिन एक बार सवाल तो उठ ही गए हैं। बिहार में भारी तादाद में वोटरों का मतदाता सूची से नाम गायब होना बड़ा सवाल है। राहुल गाँधी की वोट अधिकार यात्रा युवाओं, किसानों और गरीब तबके के हक को सामने रखकर उन्हें जागरूक करने का अभियान है। राहुल का फोकस यह दिखाने पर है कि केंद्र सरकार, लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। बिहार में उनकी यात्रा का असर खासकर युवाओं और वंचित तबकों पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी की यह यात्रा, वोट में कितना तब्दील हो पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन राहुल गांधी की निडर और जमीनी पॉलिटिक्स ने एक नई बहस को जन्म दिया है और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं जिस पर नए सिरे से हमें विचार करने की आवश्यकता है।

बिहार बंद की राजनीति ने सियासत को और गरमा दिया। विपक्ष ने इसे जनता की आवाज बताया तो सत्ता पक्ष ने इसे महज राजनीतिक नाटक करार दिया। बंद का असर पटना से लेकर जिला स्तर तक देखा गया। जनता खासकर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आक्रोशित है लेकिन इस बंद को लेकर जनता बेहद परेशान दिखी और लोगों में बेहद आक्रोश देखा गया। जनता इस तरह की राजनीति पर भी काफी नाराज है। लोग सत्ता और विपक्ष में बंटे दिखाई दिए।

बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार की गति बेहद धीमी है। विकास की घोषणाएं तो बहुत हुईं लेकिन जमीन पर असर नगण्य दिखा। यही कारण है कि जनता में नाराजगी बढ़ रही है। बिहार की चुनावी राजनीति पर नीतीश का जादू कितना चलेगा, अभी इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं उन्हें कमतर आंकना भी विपक्ष की भूल होगी।

फ़िक्की द्वारा पैग़म्बर-ए-इस्लाम पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में गूँजा अमन और इत्तेहाद का संदेश

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के नया मोहल्ला स्थित हसीन महल समुदाय भवन में फ़ेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन (फ़िक्की) द्वारा 'पैग़म्बर-ए-इस्लाम, अमन और इत्तेहाद के पैग़म्बर' विषय पर छठी वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। फ़िक्की के फ़ाउंडर चेयरमैन डॉ॰ मुश्ताक़ अंसारी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के विद्वान, समाजसेवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भाई चारा समिति के अध्यक्ष भाई मेहरबान कुरैशी ने की। मंच संचालन का दायित्व मशहूर शायर दानिश अय्यूबी और मौलाना अब्दुल माजिद मज़ाहिरी ने निभाया। क़ारी फज़लुर्रहमान द्वारा तिलावत कुरान से कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई उसके बाद नात-ए-पाक का कलाम पेश करने का सम्मान विश्व विख्यात माजिद देवबंदी और शरफ नानपारवी को प्राप्त हुआ।

इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मेहंदी हसन एनी क़ासमी (देवबंद), नूरुल्लाह मस्जिद आराम पार्क के इमाम मुफ़्ती सालिम क़ासमी, भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज, मुफ़्ती नासिर मज़हरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति चीफ़ एडवाइज़र परमजीत सिंह चंधोक आदि वक्ताओं ने अपने ख़यालात का इज़हार किया।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पैग़म्बर-ए-इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अमन, भाईचारे और एकता का पैग़ाम दिया। आज जब समाज विभिन्न चुनौतियों और तनावों का सामना कर रहा है, तब पैग़म्बर साहब की शिक्षाएँ हमें सही दिशा देती हैं। यह सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि अगर विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग साथ आएँ तो समाज में शांति और इत्तेहाद को और अधिक मज़बूती दी जा सकती है।

कार्यक्रम की सफलता में सर्वोकॉन, एफएमएस इंफ्राटेक, आयाज़ इत्र, सर्वोस्टेप, पीस ऑलवेज़ ट्रस्ट, ताज फ़ाउंडेशन और सोनम एक्सपोर्ट्स जैसे सहयोगी संस्थानों का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। अंत में सभी मेहमानों को सामूहिक दावत-ए-ख़ुशगवार पेश की गई।

कठोर फैसलों के साये में नरम शब्द : रिश्तों का द्वंद्व

वैश्विक मंच पर तूफान की तरह उभरे डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित छवि ने भारत-अमेरिका संबंधों को अनिश्चितता के भंवर में ला खड़ा किया है। अपने दूसरे कार्यकाल में, ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर न केवल आर्थिक रिश्तों को झटका दिया, बल्कि वैश्विक कूटनीति के समीकरणों को भी उलट-पुलट कर रख दिया। फिर भी, इस तनावपूर्ण माहौल में भारत की कूटनीति ने दृढ़ता, संयम और रणनीतिक दूरदर्शिता की ऐसी मिसाल कायम की, जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगी। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को "अच्छा दोस्त" कहकर रिश्तों में गर्मजोशी का इजहार किया, मगर उनके आक्रामक फैसले इस दोस्ती पर साये डालते हैं। भारत ने इस चुनौती का जवाब अपनी स्वतंत्र नीतियों और अटल संकल्प के साथ दिया, वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए कूटनीति का एक नया, प्रेरणादायी अध्याय रचा।

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, उनकी "अमेरिका फर्स्ट" विचारधारा से संचालित, व्यापार और कूटनीति में सौदेबाजी के आक्रामक रुख को उजागर करती हैं। भारत पर थोपा गया 50 प्रतिशत टैरिफ और रूस से तेल आयात पर उनकी खुली नाराजगी एक ऐसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें थोपने का प्रयास करते हैं। यह भारत के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि यह न केवल निर्यात को प्रभावित करता है, बल्कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी आघात पहुंचाता है। फिर भी, भारत ने अपनी लाल रेखाएं स्पष्ट करते हुए ट्रंप की मांगों को दृढ़ता से खारिज किया, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए कूटनीतिक ताकत का परिचय दिया। यह अडिग रुख भारत की उस कूटनीति को रेखांकित करता है, जो वैश्विक दबावों के सामने झुकने के बजाय अपने सिद्धांतों पर अटल रहती है।

ट्रंप का रवैया उनके पहले कार्यकाल से कहीं अधिक आक्रामक और एकतरफा हो चला है। उनकी नीति-निर्माण प्रक्रिया अब पूरी तरह व्यक्तिगत हो चुकी है, जहां सलाहकार उनकी हर बात पर हामी भरते हैं और वैकल्पिक दृष्टिकोण रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। भारत पर टैरिफ और रूस से तेल आयात की आलोचना इस बात का प्रमाण है कि उनके फैसले तर्क से अधिक उनकी व्यक्तिगत जिद पर टिके हैं। लेकिन भारत ने इस अनिश्चितता का जवाब एक परिपक्व, बहु-आयामी और दूरदर्शी कूटनीति के साथ दिया। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में, भारत ने चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर यह जाहिर किया कि वह किसी एक देश की कठपुतली नहीं है। यह साहसिक कदम भारत की स्वतंत्र और संतुलित कूटनीति का प्रतीक है, जो वैश्विक मंच पर उसकी साख को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को "अच्छा दोस्त" कहने का बयान भले ही रिश्तों में गर्मजोशी का आभास देता हो, लेकिन उनके आक्रामक फैसले इस दोस्ती को सतही और खोखला साबित करते हैं। भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को दृढ़ता से ठुकराया और व्यापार समझौतों में अपनी शर्तों पर अटल रहा, जिसने ट्रंप की नाराजगी को और भड़काया। फिर भी, भारत के प्रधानमंत्री ने इस जटिल परिस्थिति को असाधारण कूटनीतिक कुशलता के साथ संभाला। उन्होंने न केवल ट्रंप के बयान की कूटनीतिक सराहना की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भारत की नीतियां किसी

बाहरी दबाव से डगमगाएं नहीं। जवाबी शुल्क लगाकर और विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका की नीतियों को चुनौती देकर भारत ने अपनी अडिग स्थिति स्पष्ट कर दी। यह साहसिक कदम भारत की कूटनीति को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जो वैश्विक दबावों के सामने झुकने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखता है।

ट्रंप की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से स्टील, एल्युमिनियम और कृषि क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा है। उनकी कठोर आव्रजन नीतियां भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों, पेशेवरों और छात्रों के लिए अवसरों को संकुचित कर सकती हैं। लेकिन भारत ने इस संकट को एक सुनहरे अवसर में बदल दिया। नीति आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने इसे "पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर" करार दिया, जिसका उपयोग भारत ने अपनी आर्थिक सुधारों को गति देने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया। यह दृष्टिकोण भारत के आर्थिक और कूटनीतिक लचीलेपन को रेखांकित करता है, जो ट्रंप जैसे अप्रत्याशित नेताओं के सामने भी अपनी नीतियों को दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ लागू करता है, वैश्विक मंच पर अपनी साख को और मजबूत करता हुआ।

भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अटल स्वायत्तता और सूक्ष्म संतुलन है। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के बावजूद, भारत ने न केवल उनके साथ रिश्तों को कुशलता से संभाला, बल्कि अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ किया। यह कूटनीति न सिर्फ भारत के राष्ट्रीय हितों की प्रखर रक्षक है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी साख को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ट्रंप की अप्रत्याशित और उत्तेजक नीतियां भले ही तीखी चुनौतियां पेश करें, लेकिन भारत ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह हर तूफान का सामना करने को न केवल तैयार है, बल्कि उसमें से विजयी होकर उभर सकता है। चाहे "अच्छा दोस्त" वाला बयान हो या टैरिफ का दबाव, भारत की कूटनीति ने हर मोर्चे पर अपनी अजेयता और श्रेष्ठता का परचम लहराया, वैश्विक मंच पर एक स्वर्णिम इतिहास रचते हुए।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने मृतक महिला प्रवीण के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी

अमृतसर, 6 सितंबर (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज कटड़ा जयमल सिंह में गली भाटरिया में भारी बरसात के कारण मकान की छते गिरने से मारे गई बुजुर्ग महिला प्रवीण कुमारी के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक डॉ गुप्ता ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम इस प्राकृतिक आपदा में परिवार की हर संभव सहायता करेंगे और फिलहाल हमने 4 लाख रुपये का चेक दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक महिला की बेटी को सरकारी नौकरी दिलवाले का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि घर को बनवाने के लिए भी सहायता की जाएगी। इस अवसर पर पार्षद जरनेल सिंह ढोट, गुरदास सिंह, मनजीत सिंह, सुरजीत बिट्टू दोधी, चरणजीत सिंह, दीपक चड्ढा, सुदेश कुमार और आम आदमी पार्टी के वॉलिंटियर्स मौजूद थे।

शिक्षक दिवस पर बिहार की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार का विशेष

▪ शिक्षक दिवस एक्सक्लूसिव क्विज प्रतियोगिता एवं काव्यांजलि (काव्य गोष्ठी) आयोजित की गई।

पटना। शिक्षक दिवस के अवसर पर टीचर्स ऑफ बिहार ने एक भव्य एवं सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस विशेष आयोजन में "शिक्षक दिवस एक्सक्लूसिव क्विज प्रतियोगिता" तथा "काव्यांजलि (कविता संध्या)" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने शिक्षक दिवस से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं काव्यांजलि में शिक्षकों ने कविताओं के माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा, शिक्षा के महत्व और समाज में शिक्षक की भूमिका को अभिव्यक्त किया।

टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा जगत में शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना और शिक्षकों की गरिमा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना रहा।

टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलती है।

शिक्षक दिवस एक्सक्लूसिव क्विज प्रतियोगिता के सफल आयोजन में मृत्युंजय कुमार एवं काव्यांजलि के सफल आयोजन में रामकिशोर पाठक का सराहनीय योगदान रहा।

दोनों कार्यक्रम में शामिल 8000 से अधिक प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदेश प्रवक्ता रंजेश कुमार एवं प्रदेश मीडिया संयोजक मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वत किया की भविष्य में भी इसी तरह के शैक्षिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा।

करमजीत सिंह रिंटू ने बारिश के कारण रुके विकास कार्य शुरू करवाए

बरसात से जनता को आई दिक्कतों का होगा समाधान : करमजीत सिंह रिंटू

अमृतसर, 7 सितम्बर (साहिल बेरी)

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन और विधानसभा उत्तर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात के कारण विकास कार्य रुक गए थे, जिन्हें अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। रिंटू ने कहा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बारिश के चलते जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उनका समाधान किया जाएगा।

रिंटू ने आज वार्ड नंबर 9 क्षेत्र के शास्त्री नगर गोपाल मंदिर के पास गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग लंबे समय से टूटी गलियों की समस्या से जूझ रहे थे। अब उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। जल्द ही गलियों का निर्माण पूरा होने पर स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। रिंटू ने यहां के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर साहिल सागर, बॉबी सरीन, गुरिंदर गोरा, जसविंदर सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

करमजीत सिंह रिंटू ने विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ग्राम पंचायत चांद एवेन्यू सेक्टर-2 की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बारिश के कारण यह काम रुका हुआ था। इस अवसर पर रिंटू ने पंचायत से भी मुलाकात कर बारिश से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच वीना मेहरा, प्रधान अजय नंदा, पंच राकेश खन्ना, चंदनपाल सिंह, राकेश पाठक, संदीप लाहौरिया, सारथी मेहरा, महेश मुखीजा, डॉ. पुंज, प्रणव धवन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

इसके साथ ही कर्मजीत सिंह रिंटू ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौशहरा खुर्द एन्क्लेव में पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने घर-घर जाकर जनता की समस्याओं को समझा और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सीवरेज, सभी सड़कों और गलियों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और बारिश से क्षतिग्रस्त कुछ इमारतों को दोबारा बनाया जाएगा।

रिंटू ने कहा कि भारी बारिश से आई समस्याओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब की जनता के साथ खड़े हैं। इस मौके पर सेठ एन्क्लेव वेलफेयर सोसायटी के प्रधान आदित्य, उप प्रधान जसप्रीत सिंह, महासचिव अमित गोस्वामी, सचिव साक्षी खन्ना, चंद्र प्रकाश और इलाके के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023